सर्वहारा दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-27 अंक-2 22 जनवरी से 5 फरवरी, 2012 मुख्य संपादक - कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती मूल्य : 2 रुपये

14 मार्च को दिल्ली चलो
संसद पर अखिल भारतीय प्रदर्शन में शामिल हों

जनजीवन की ज्वलन्त मांगों को लेकर एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) 14 मार्च को संसद पर अखिल भारतीय विशाल रैली करने जा रही है। इस दिन देश भर से आये हजारों लोग दिल्ली के राजपथ को गुंजा देने वाली आवाज बुलन्द करेंगे। लोगों की दुर्दशा देख कर भी केन्द्र की कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी है। जन आन्दोलन के जरिए सरकार पर मांगे मानने के लिए दबाव डाल कर लोगों को जरूरी राहत प्रदान करने की खातिर पार्टी ने पूरे देश में संघर्ष का बिगुल बजा दिया है।

आकाशछूती महंगाई ने अनिश्चित व सीमित आय वाले लोगों का जीना दूभर कर दिया है। गरीब लोगों के लिए भुखमरी की नौबत पैदा हो गई है जबकि सरकारी गोदामों में लाखों टन अनाज पड़ा सड़ रहा है। सरकार व प्रशासन की मिलीभगत से जमाखोरी, कालाबाजारी व सट्टेबाजी बेलगाम जारी है। बेरोजगारी विकराल रूप लेती जा रही है। बेरोजगार दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। छंटनी-तालाबंदी हो रही है। मजदूर-कर्मचारियों की नौकरियां छीनी जा रही हैं। असल वेतन घट रहा है। काम का बोझ बढ़ रहा है। इन सब के खिलाफ लोग कहीं कोई प्रतिवाद, आन्दोलन न कर सकें इसलिए जनवादी अधिकार छीनने की स्वेच्छाचारी साजिशें रची जा रही हैं। श्रम कानूनों का सरेआम उल्लंघन हो रहा है।

खेतीबाड़ी से जुड़े आबादी के ज्यादातर हिस्से की तरफ सरकार घोर उपेक्षा बरत रही है। उपजाऊ कृषि भूमि का कोड़ियों के भाव जबरन अधिग्रहण कर पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है। किसान-खेतमजदूरों को उजाड़ा जा रहा है। खाद, बीज, कीटनाशकों, डीजल-पेट्रोल, मटिया तेल, बिजली आदि कृषि उपयोगी सामग्री के दाम बेतहाशा बढ़ते जाने से कृषि में लागत खर्च बढ़ता जा रहा है। वाजिब दामों पर फसलों की सरकारी खरीद न होने से व्यापारियों को कौड़ियों के भाव बेचना पड़ता है जिससे किसान कर्जजाल में फंसते जा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक आये साल 20-25 हजार किसान आत्महत्या कर

(शेष पृष्ठ 2 पर)

ईरान पर संभावित अमेरिकी युद्ध के खतरे को परास्त करें

कपटपूर्ण बहानों की आड़ में इराक पर कब्जा जमाने के तुरन्त बाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद ने ईरान को ''दुष्ट राष्ट्र'' की संज्ञा दे दी थी और जिसे वे 'बुराइयों की धुरी' कहते हैं उसका एक घटक बता दिया था जिसमें अन्य दो देश समाजवादी क्यूबा व उत्तरी कोरिया शामिल हैं। तभी से वे एक पर एक जाल बुन रहे हैं ताकि ईरानी हुकूमत को झुकाया जा सके और उनके आदेशों के सामने घुटने टेकने को मजबूर किया जा सके। यू.एन.ओ. जो अब असल में उनकी रबर स्टैम्प बन गया है उससे अनुमोदन हासिल करके अमेरिकी साम्राज्यवादी शासकों ने ईरान पर कठोर आर्थिक प्रतिबन्ध थोप दिए हैं। तब से लेकर वे आरोप लगाते आ रहे हैं कि ईरान उच्च स्तर पर न्युक्लियर क्षमताओं को विकसित कर रहा है यहाँ तक कि वह एटम बम बनाने के नजदीक है, जिससे उनके अनुसार पश्चिमी एशिया में शांति व सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। बाद में उन्होंने अपने युरोपियन साम्राज्यवादी-पूँजीवादी सहयोगियों के साथ मिलकर इन्टरनेशनल एटोमिक एनर्जी एजेंसी (आई.ए.ई.ए.) की एक महत्वपूर्ण बैठक में यह आरोप लगाते हुए एक प्रस्ताव पेश किया कि आणविक अप्रसार संधि (एन.पी.टी.) का हिस्सा होते हुए भी ईरान अनेक बार एन.पी.टी. के तहत सुरक्षा उपायों के समझौते की अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने में असफल रहा और इसने आई.ए.ई.ए. के विधि-विधानों का उल्लंघन किया है। इसके साथ-साथ उन्होंने पुरजोर ढंग से ईरान पर कपटपूर्ण आरोपों की झड़ी लगा दी जैसे कि इसने वॉशिंगटन में सऊदी अरब के राजदूत की हत्या का षड़यन्त्र रचा इत्यादि। पश्चिम एशिया में अपने प्रतिनिधि, इसके मुखौटे न सही, लेकिन निकटतम सहयोगी उग्र यहूदीवादी इज़राइल के साथ मिलकर अमेरिकी साम्राज्यवाद लम्बे अरसे से ईरान पर सैनिक आक्रमण करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए यह झूठी अफवाह फैला रहा है और कपोल-कल्पित दैत्य की कहानी लिखने की तरह मनगढ़ंत आरोपों की झड़ी लगा रहा है जैसा कि इसने इराक पर कब्जा जमाने के लिए किया था और बंदूक की नोक पर लिबिया में तख्तापलट को अंजाम देने में किया था। नाटो बलों को लीबिया पर झपट पड़ने के लिए संचालित करने, प्रेसिडेन्ट गद्दाफी की हत्या करने और वहाँ कठपुतली शासन कायम करने के बाद अमेरिकी शासकों ने अब ईरान-विरोधी अपना अभियान तेज करने की तरफ ध्यान केन्द्रित कर दिया है, इस बात की पूरी-पूरी आशंका है कि ईरान के खिलाफ सम्पूर्ण युद्ध छेड़ने का यह पूर्वाभ्यास है। पश्चिम एशिया का अन्य एक देश सीरिया जो उनके आदेशों के सामने नतमस्तक होने से मना कर रहा है वह भी इनकी हिट लिस्ट पर है।

ईरान को कुचलने के लिए अमेरिकी साम्राज्यवादी इतने उतावले क्यों?

जो विश्व घटनाओं पर नजदीक से गौर कर रहे हैं और व्यापक जनवादी नजरिया रखते हैं उनके लिए अमेरिकी साम्राज्यवादियों के मंसूबों को समझना कोई मुश्किल बात नहीं है। हालाँकि पहले स्टालिन के बाद रूस में और फिर माओ त्से-तुंग के बाद चीन में संशोधनवादी नेतृत्व सत्ता पर काबिज हो जाने के चलते बहुत सारी कमियों और कमजोरियों का शिकार होने के बावजूद एक सशक्त समाजवादी खेमा युद्ध के खिलाफ शांति के एक गढ़ के रूप में काम कर रहा था, इसके ढह जाने के बाद अमेरिकी साम्राज्यवादियों ने एक सम्राट की तरह पूरी दुनिया पर शासन करने के लिए अधिकृत सुपर-अथोरिटी की भूमिका खुद अपने ऊपर आयद कर ली। कोई भी देश उनके फरमान को मानने या उनके आदेश का पालन करने से मना करता है तो उसे तुरन्त 'शान्ति व जनतंत्र का दुश्मन' करार दे दिया जाता है और सैनिक हस्तक्षेप तथा तूफानी हमले का निशाना बनाया जाता है। हर कोई जानता है कि अन्य बातों के अलावा, अपने अधिकतम मुनाफे और तेल के उत्पादन व वितरण पर कब्जे के प्रयासों में भीमकाय तेल महाकम्पनियों ने दूसरे विश्वयुद्ध के बाद अमेरिकी साम्राज्यवाद के सामरिक व आर्थिक उदय में वित्तीय सहायता प्रदान की थी। एकध्रुवीय विश्व में अमेरिकी साम्राज्यवादी व उनके सहयोगी पश्चिम एशियाई देशों के तेल समृद्ध क्षेत्रों पर अपना पूर्ण नियन्त्रण स्थापित करने के प्रयास में अपने आर्थिक व सामरिक दबदबे का इजहार कर रहे हैं।

(शेष पृष्ठ 5 पर)

प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक की एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) द्वारा कड़ी निन्दा
लोगों के संकट के साथ एक मजाक

एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के महासचिव कॉमरेड प्रभाष घोष ने 22 दिसम्बर, 2011 को संसद में पेश किये गये खाद्य सुरक्षा विधेयक पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए 27 दिसम्बर, 2011 को निम्नलिखित बयान जारी किया:

देशवासियों को भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के नाम पर कांग्रेस के नेतृत्व वाली केन्द्र की यूपीए सरकार द्वारा जो विधेयक संसद में पेश किया गया है वह यकीनन भूख से पीड़ित गरीबों व वंचितों की तीव्र पीड़ा को कम करने का एक ईमानदार प्रयास तो बिल्कुल है ही नहीं बल्कि पूरे जोरशोर से शुरू की गई केवल एक नौटंकी मात्र है। खाद्यान्नों का निर्धारित कोटा 46 प्रतिशत ग्रामीण और 26 प्रतिशत शहरी आबादी के लिए सिर्फ 7 किलोग्राम अनाज और बाकी ग्रामीण व शहरी आबादी के लिए 4 किलोग्राम अनाज का आबंटन और वह भी इसके क्रमशः 90 प्रतिशत व 50 प्रतिशत से अधिक के लिए नहीं, एक क्रूर मजाक है। जिन्दा रहने के लिए कम से कम 15 किलोग्राम की अलघुकरणीय न्यूनतम आवश्यकता पड़ती है। यह उससे निहायत कम है, यहां तक कि पूरी तरह भ्रष्ट कार्यान्वयन मशीनरी के कारण घोषित अल्प लाभ भी वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचते नहीं हैं जैसाकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, अंत्योदय अन्न योजना, एकीकृत बाल विकास योजना, और ऐसी ही अन्य योजनाओं के मामले में देखा गया है। लम्बे अर्से से लोगों द्वारा माँग की जाती रही है कि सरकार को खाद्यान्नों की खरीद और वितरण दोनों की प्रत्यक्ष और मुकम्मल जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेनी चाहिए लेकिन यह तय है कि प्रस्तावित विधेयक ने समस्या के हासिये को भी नहीं छुआ है और इस तरह यह एक चकमा मात्र हो जाएगा। इस तरह के एक कॉस्मेटिक विधेयक को लाने का उद्देश्य लोगों को धोखा देने के जरिए आगामी चुनावों की पूर्वसंध्या पर सत्तारूढ़ कांग्रेस को चुनावी लाभ प्रदान करना है।

इसलिए हमारा मेहनतकश लोगों से आग्रह है कि सभी खामियों व प्रशासन की संगीन भूल-चूकों को दूर करने और उसे टोन अप करने तथा जरूरतमंद, भूखे व बेसहारा लोगों को वास्तव में कुछ राहत प्रदान करे ऐसा एक उचित और प्रभावी खाद्य सुरक्षा विधेयक का अधिनियमन सुनिश्चित करने के लिए देश भर में एक जोरदार जनवादी आन्दोलन विकसित करने के जरिए सरकार को मजबूर कर दें।

दिल्ली चलो.....

(पृष्ठ 1 का शेष)

लेते हैं। खुदरा व्यापार से जुड़े लोगों पर भी देशी-विदेशी बड़ी पूंजी का हमला जारी है।

शिक्षा-स्वास्थ्य के निजीकरण-व्यापारीकरण से इलाज खर्च और फीस बढ़ती जा रही हैं और ये आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। 8वीं तक बिना परीक्षा पास करने का फतवा जारी कर दिया गया है जिससे शिक्षा की बुनियाद ही कमजोर की जा रही है। केन्द्र की कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार द्वारा लाया गया शिक्षा के अधिकार का कानून असल में शिक्षा को छीनने का कानून है। देश के मजदूर आन्दोलन की मांग को धता बताते हुए असंगठित क्षेत्र मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा की मांग मानना तो दूर सरकार ने संघर्षों से अजि।त पेंशन के अधिकार को खत्म कर पेंशन को अंशदार्या बना दिया। पेंशन फण्ड को निजी खिलाड़ियों के हवाले करने के लिए पी.एफ.आर.आर.डी.ए. बिल को पास कराने की साज़िश की जा रही है।

युवा पीढ़ी की नैतिक-सांस्कृतिक रीढ़ को तोड़ डालने की साजिश के तहत शराबखोरी, नशाखोरी, जुएबाजी, अश्लीलता की बाढ़ सी ला दी है। महिलाओं की इज़्ज़त-आबरू सुरक्षित नहीं है। अपराध व अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। महिलाओं व बच्चों की खरीद-बेच हो रही है। हर स्तर पर भ्रष्टाचार, रिश्वत व भाई-भतीजावाद का बोलबाला है। बेईमान अफसर व भ्रष्ट नेता अपना घर भर रहे हैं। घोटालेबाज साफ बच निकलते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत लोकपाल कानून बनाने की मांग को सरकार तरह-तरह के बहाने बना कर टाल रही है।

इन दमघोंटू हालात से निजात कैसे मिल सकती है? क्या चुनाव इसका इलाज है या सरकारों की अदला-बदली इसका वाकई कोई हल है? यह तो बहुत बार हो चुका है। क्या इससे यह असहनीय हालत कुछ भी बदली है? उन सब पाटियों के उम्मीदवार जो अपने को 'जनसेवक' कहकर, झूठे वायदे करके, जातपात व साम्प्रदायिकता फैला कर, धनबल, प्रचारबल व बाहुबल से जनता को प्रभावित कर चुनावों में वोट बटोर लेते हैं। वे केवल वोट के पंछी हैं। वोट लिये और फुर्र। चुनाव हो जाने के बाद फिर वे 5 साल नजर नहीं आते हैं। ये 'जनसेवक' एमपी, एमएलए बनकर सरकार की जनविरोधी नीतियां लागू करते हुए पूंजीपतियों के चहेते और जनता की नफरत के पात्र बन जाते हैं। फिर उनके खाली स्थान को भरने के लिए कोई दूसरा नया धोखेबाज 'जनसेवक' का भेष धारण करके आ जाता है। आजादी के 64 साल से यही बार-बार होता आया है। अपने आप सरकार लोगों की इस दुर्दशा को कम करने के लिए कभी सक्रिय नहीं हुई। जो भी पार्टी सरकार में आई, उसने सिर्फ इतना ही नहीं कि पूंजीपतियों की ताबेदारी की और जनविरोधी नीतियां लागू की हैं, बल्कि तमाम समस्याओं, संकटों व दुख-तकलीफों की जड़ इस पूंजीवादी शोषणमूलक व्यवस्था को ही परवान चढ़ाया है और लोगों की दुर्दशा को और भी बढ़ाया है। सरकार की इन जनविरोधी नीतियों को रोकने लायक कोई जोरदार आन्दोलन न होने से शासक वर्ग बेरोकटोक इन जनविरोधी नीतियों को लागू करता जा रहा है।

जनता को इन दमघोंटू हालात से निजात दिलाने के लिए एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) की केन्द्रीय कमेटी ने अपने दम पर पहलकदमी लेते हुए देशव्यापी जोरदार आन्दोलन खड़ा करने का बीड़ा उठाया है। पार्टी नेताओं-कार्यकर्ताओं के सामने यह एक जबरदस्त चुनौती है। जनता को शामिल कर आन्दोलन को ताकतवर बनाने का एक प्रयास जारी है। यह आन्दोलन ही जनता का रक्षाकवच है। इस महारैली को सफल करने के लिए पार्टी कार्यकर्ता तनदेही से जुटे हुए हैं। जगह-जगह सभएं हो रही हैं। इस कार्यक्रम पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए लोग दिल खोल कर चंदा दे रहे हैं। प्रधानमत्री को सौंपे जाने वाले मांग पत्र पर हस्ताक्षर अभियान जोरशोर स जारी है। इस हस्ताक्षरित मांग पत्र को लेकर दिल्ली में 14 मार्च, 2012 को संसद पर प्रदर्शन कर जोरदार आवाज बुलन्द की जायेगी। इसमें शामिल होने की पार्टी ने लोगों से अपील का है। आइये, देश भर में हम सब आवाज में आवाज मिला कर कह दें कि हम हैं 99 प्रतिशत और तुम हो एक प्रतिशत। अब तुम हमें दबा कर नहीं रख सकते। तुम्हें हमारी मांगें माननी ही पड़ेंगी।

छठा बिहार राज्य छात्र सम्मेलन

पटना (बिहार): पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप, शिक्षकों की भारी कमी, शुल्क वृद्धि, यौन शिक्षा, छात्र संघ चुनाव नहीं कराये जाने और शैक्षणिक अराजकता व भ्रष्टाचार के खिलाफ दो दिवसीय ऑल इंडिया डी एस ओ का छठा बिहार राज्य छात्र सम्मेलन सम्पन्न हुआ। सम्मेलन के खुले सत्र को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रदर्शन के रूप में किया गया। विभिन्न जिलों से आये हजारों छात्रों का सुसज्जित जुलूस गांधी मैदान से निकला, जो फ्रेजर रोड, डाक बंगला चौराहा, स्टेशन गोलम्बर, मीठापुर होते

हुए आर ब्लॉक पहुंचा। इस मौके पर एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) राज्य कमिटी के वरिष्ठ सदस्य कॉ0 अरुण कुमार सिंह ने कहा कि ''पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप दरअसल व्यापारीकरण-निजीकरण का पर्याय है। आज चाहे वह सुशासन का राग अलापने वाली राज्य की नीतीश सरकार हो या फिर केन्द्र में कांग्रेस-नीत यूपीए की सरकार, दोनों ने शिक्षा को व्यापार की वस्तु बना दिया है। शिक्षा का अवसर कुछ मुट्ठीभर लोगों तक सिमट कर रह गया है। देश के हर नागरिक को शिक्षा का अवसर प्राप्त हो-इसके लिए ताकतवर आंदोलन की जरूरत है।'' वहीं ऑल इंडिया डीएसओ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कॉ0 सुब्रत गौरी ने कहा कि ''आज शिक्षा के मूल मकसद इंसान निर्माण, चरित्र गठन से हटाकर उसे पूरी तरह से मुनाफा कमाने वाली वस्तु में तब्दील किया जा रहा है।'' सभा को ऑल इंडिया डीएसओ उत्तर प्रदेश राज्याध्यक्ष झरना मालवीय, बिहार राज्याध्यक्ष साधना मिश्रा, राज्य सचिव सूर्यकर जितेन्द्र, राज्य उपाध्यक्ष अनामिका, उमा शंकर सहित सचिव मंडल सदस्य अनिल कुमार ने भी संबोधित किया।

प्रतिनिधि सत्र अंजुमन इस्लामिया हॉल में आयोजित हुआ। ऑल इंडिया डीएसओ के 6ठे राज्य सम्मेलन के प्रतिनिधि सत्र का उद्घाटन करते हुए प्रख्यात अर्थशास्त्री तथा जेएनयू के सेवानिवृत्त प्राध्यापक प्रो. ईश्वरी प्रसाद ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार एक तरफ ग्रोथ और विकास का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ देश में लाखों किसान आत्महत्या कर रहे हैं। शहर के चौराहों पर सुबह-सुबह मजदूरों की भारी भीड़ दिख रही है, लोगों को काम नहीं मिल रहा है। अपनी शैक्षिक समस्याओं के निदान की मांग पर कड़ाके की ठंढ़ में भी जोश और उमंग के साथ सम्मेलन में शिरकत कर राज्य के विभिन्न जिलों से आये छात्र-छात्राओं की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखते हुए उन्होंने कहा कि आप ही नया देश, नया समाज बना सकते हैं। वहीं एआईडीएसओ के महासचिव सौरभ मुखर्जी ने कहा कि कभी राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कहकर, कभी युद्ध थोपे जाने का भय दिखाकर और कभी आतंकवाद के खात्मे के नाम पर पुलिस और सामरिक बजट में तथा मंत्रियों, सांसदों, विधायकों एवं नौकरशाहों की सुरक्षा और अन्य खर्चो में लगातार इजाफा जारी है। जबकि विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और स्कूली शिक्षा के कोष में कमी का बहाना बनाकर लगातार शिक्षा बजट में कटौती हो रही है। देश की जनता को शिक्षा प्रदान करने की अपनी जिम्मेवारी से सरकार पीछे हट रही है।

छात्र प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए मुख्यवक्ता एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के उत्तर प्रदेश राज्य कमिटी के वरिष्ठ सदस्य तथा एआईडीएसओ के पूर्व महासचिव स्वपन चटर्जी ने कहा कि बिहार तथा पूरे देश में शासक वर्ग द्वारा आम छात्रों से शिक्षा को छीनने की साजिश का पर्दाफाश कर सबके लिए शिक्षा के समान अवसर मुहैया कराने की एकमात्र गारंटी है-सही दृष्टिकोण पर आधारित छात्र आंदोलन। उन्होंने शिक्षा की महत्ता पर चर्चा करते हुए कहा कि आज देश का शासक वर्ग शिक्षा-संस्कृति को ही बर्बाद करना चाहता है ताकि सामाजिक अन्याय-अत्याचार के खिलाफ आवाज न उठे सके। सम्मेलन का मूल प्रस्ताव अनिल कुमार ने पेश किया। मूल प्रस्ताव के समर्थन में रवि कुमार सिंह, ज्योति कुमारी, विजय कुमार, दिलीप कुमार, शुभम कुमार, महेन्द्र, विकाश कुमार, परवेज आलम तथा निकोलाई ने अपने विचार रखे। सांगठनिक प्रस्ताव राज्य सचिव सूर्यकर जितेन्द्र ने पेश किया जिसके समर्थन में आशुतोष कुमार, सरोज कुमार सुमन, श्याम कुमार, पिंकी कुमारी, पूजा कुमारी और पन्ना लाल ने अपनी बात रखी।

प्रतिनिधि सत्र का संचालन साधना मिश्रा, अनामिका, उमा शंकर वर्मा व अरविन्द कुमार के अध्यक्षमंडल ने किया। सम्मेलन के अंत में 36 सदस्यीय कमिटी का गठन किया गया, जिसमें सूर्यकर जितेन्द्र को अध्यक्ष, मुजाहिद आजम, रौशन कुमार रवि व विकास कुमार को उपाध्यक्ष, अनिल कुमार को सचिव, आशुतोष कुमार को कोषाध्यक्ष तथा पुष्पा कुमारी को कार्यालय सचिव चुना गया।

उत्साह के साथ मनायी सावित्रीबाई फूले जयंती

नागपुर (महाराष्ट्र) : महान समाज सुधारक सावित्रीबाई फूले की 180वीं जयंती पर अखिल भारतीय महिला सांस्कृतिक संगठन (एआईएमएसएस) की नागपुर शाखा की ओर से 3 जनवरी को स्थानीय भुरे भवन बैद्यनाथ चौक पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता संगठन की जिला अध्यक्ष कॉमरेड नंदिनी भोंडे ने की। सभा को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं के सामाजिक सांस्कृतिक व राजनैतिक तौर पर जागृत और पूरा समाज शोषण से मुक्त हुए बिना महिलाओं को मुक्ति मिलना असम्भव है। सावित्रीबाई फूले का सपना यही था। मुख्य वक्ता प्राचार्या श्रीमती नैया ने कहा कि अगर महिलाएं अच्छी सोच-विचार से लैस होकर समाज परिवर्तन के लिए आगे आयें तो वे समाज परिवर्तन की सूत्रधार बन सकती हैं। मुख्य अतिथि श्रीकांत रायपुरे थे। मीरा गिरी, संगीता बमणे, यशोदा दमे, उषा निकोसे, रेखा रंगारी आदि ने भी अपने विचार रखे। कुमारी ज्योति ठाकरे ने प्रस्तावना रखी और कुमारी विद्या गुरनुले ने सभा का संचालन किया व आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में स्पंदननगर, रामबाग, इमामबाड़ी परिसर की महिलाएं शामिल हुई।

दिल्ली विश्वविद्यालय में रामानुजम का 'रामायण' लेख हटाना लोकतंत्र व धर्मनिरपेक्षता का मज़ाक और इतिहास-निष्ठा पर प्रहार

दिल्ली विश्वविद्यालय की अकेडमिक काउन्सिल ने हाल ही में जाने माने विद्वान रामानुजम द्वारा लिखित 'थ्री हण्ड्रेड रामायण, फाइव एग्जाम्पल्स एण्ड थ्री नोट्स ऑन ट्रांसलेशन' शीर्षक वाले लेख को स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम से हटाने का फैसला ले लिया है। देश भर में जाने माने शिक्षविदों व इतिहासकारों के साथ-साथ धर्मनिरपेक्ष, वैज्ञानिक व जनवादी शिक्षा से जो जरा भी वास्ता रखने हैं उन लोगों ने इस कार्रवाई के खिलाफ बड़े साफ शब्दों में अपना विरोध दर्ज कराया है और इसकी कड़ी निन्दा की है। देश के शिक्षित लोगों को इस फैसले के पीछे एक अशुभ, घिनौनी साजिश होने का अन्देशा है। सवाल उठता है कि पूर्वकथित इस बात को लेकर ठीक अब इसी समय सक्रिय होने की क्या जरूरत आ पड़ी थी? इसके लिए जरूरत है ठण्डे दिमाग से तर्कसंगत ढंग से इस कदम की बारीकी से जांच-परख की जाये।

बात को सीधी करने के लिए यह कहना पड़ेगा कि रामानुजम की रचना में ऐसी नई कोई भी जानकारी या नया विचार नहीं पेश किया गया है जिस पर इससे पहले किसी ने सरसरी तौर पर प्रकाश न डाला हो। अपनी मूल बात में रामानुजम का यह मानना है कि रामायण कोई एक नहीं है, बहुत सारी रामायण प्रचलित हैं और वे न केवल एक दूसरी से भिन्न हैं बल्कि कहीं-कहीं तो वे एकदम विपरीत भी हैं। उन्होंने कुछ रामकथाओं से उद्धरण देते हुए दिखाया है कि कम्बन द्वारा रचित ईरामावतारम, थाईलैण्ड में प्रचलित रामकेइन, विमलसूरी द्वारा रचित जैन रामायण, संथाल आदिवासियों में प्रचलित रामकथा और प्रचलित बाल्मिकी की रामायण जैसे इसके कई संस्करणों में गंभीर और काफी सारे फर्क हैं, यहाँ तक कि वे एक दूसरी से विरोधाभासी भी हैं। उन्होंने दिखाया है कि जैन रामायण में मूल पात्र राम नहीं बल्कि रावण है। वह सीता के प्रति प्रेमासक्त होकर उसका मन जीतने की कोशिश करता है। इससे पहले कई विद्वानों ने दिखाया है कि जातक कथाओं में जो रामकहानी है उसमें न तो रावण प्रसंग है, न ही उसके द्वारा सीता हरण या राम द्वारा रावण को हरा कर लंका से सीता को वापस लाने की कहानी है। दशरथ जातक नामक राम कथा के संस्करण में राम लंका नामक जगह पर नहीं जाता है बल्कि राज सिंहासन पर कब्जा करने के लिए राम व भरत के बीच राजमहल में रचे गये षड्यंत्र और उसके नतीजतन राम को मिले 14 साल के लिए हिमालय गमन के दसौटे को केन्द्रित करके वर्णन ही इस कहानी की मूल बात है।

कई अकेडमिक विद्वानों ने भी इसी तरह के मत व्यक्त किये हैं। हेमचन्द्र रायचौधरी ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ 'पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इण्डिया' में लिखा है कि ऋग्वेद में भी राम और दशरथ के नाम का उल्लेख मिलता है। लेकिन उसमें राम एक असुर का नाम है न कि देवता का। उन्होंने यह भी जिक्र किया है कि बौद्ध मूल के दशरथ जातक की जिस कहानी में दशरथ अयोधा का नहीं बल्कि वाराणसी का राजा है, उस कहानी में सीता राम की पत्नी नहीं बल्कि बहन है और जनक से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। इतिहासकार ए एल बैसम ने अपनी 'वण्डर दैट इज इण्डिया' पुस्तक में रामायण को 'लेजेण्ड ऑफ राम' यानी राम विषयक गाथा काव्य माना है। उन्होंने यह भी कहा है कि इस देश के एक और महाकाव्य महाभारत में प्राचीनता की विशेषता (आर्किक फीचर) रामायण से ज्यादा है। विभिन्न प्रमाणों से बैसम इस निष्कर्ष पर भी पहुंच गये हैं कि रामायण के पात्रों के नामकरण में भी आर्यपरस्त पूर्वाग्रह व पक्षपात पूर्ण रुख साफ झलकता है जिनमें द्राविड़ों सहित अनार्यों को राक्षस या असुर के तौर पर दर्शाया है।

तर्क आधारित विश्लेषण पर आश्रित रह कर आधुनिक विद्वानों ने भी रामायण में वर्णित रावण की लंकापुरी की तुलनात्मक समीक्षा करते हुए विभिन्नताओं व विराधाभासों को दर्शाया है। पुरातात्विक खनन कार्यों से प्राप्त प्रमाणों से मिला कर उन्होंने साफ तौर पर दर्शाया है कि रामायण में जिस लंकापुरी का वर्णन किया गया है उस तरह के किले, प्राचीर और खाई वाले परकोटे से घिरा हुआ सुरक्षित नगर ईसवी संवत् 8वीं सदी से पहले नहीं मिलते। इसके अलावा स्वर्णनगरी लंका की सोने की प्राचीर या शिलाखण्डों या पत्थरों से सेतुबंध बनाकर सागर पार कर उसकी जमीन पर जाने की बात भी अत्यन्त कपोल कल्पित गप ही लगती है। असल में सागर का मायना महासमुद्र नहीं बल्कि हो सकता है कि बड़ी झीलनुमा जलाशय को भी सागर कहा गया हो। इसके अलावा सिंहल द्वीप को प्राचीन काल में लंका नहीं कहा जाता था। लंका कहने का तात्पर्य किस स्थान से है इस पर अपने शोध करके पुरातत्वविद एच डी सांकलिया ने अपने 'रामायण, मिथ ऑर रियलटी' ग्रंथ में बहुत सारे सबूत पेश करके दिखाया है कि रावण की राजधानी लंका हो सकता है कि आज के मध्य प्रदेश में स्थित दण्डकारण्य या इसके निकटस्थ कोई वनांचल रहा होगा। रावण सम्भवत: एक गोण्ड या इसी तरह के किसी और कबीले का सरदार था। ये सब इस तथ्य की ओर ईशारा करते हैं कि लोकप्रिय कहानी कहने के ढंग से इस महाकाव्य में काफी सारी बातें बाद के समय में जोड़ी गई हैं।

अग्रणी भारत-तत्वविद सुनीति चटोपाध्याय ने राम कथाओं या राम कहानियों की समीक्षा व विश्लेषण करते हुए दिखाया है कि चारण कवि आम तौर पर दो अलग-अलग लोकप्रिय संस्करणों वाली गाथाएं लोगों को गाकर सुनाया करते थे। एक थी राम-भरत के बीच सिंहासन पर कब्जा करने के लिए हुए टकराव को लेकर कहानी, जो हमें दशरथ जातक में मिलती है और दूसरी कहानी थी वानर को प्रतीक चिन्ह मानने वाले गण या आदिवासी कबीले के साथ रावण के हुए टकराव की कहानी। प्रतिभावान कवि के रूप में बाल्मिकी को यह श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्होंने सीताहरण के प्रकरण को जोड़ कर इन दोनों कहानियों को एक साथ मिला कर एक अत्यन्त लोकप्रिय कहानी बना दिया है।

पिछली सदी के 70 के दशक में देश के एक दिग्गज विद्वान और अकेडमिसियन सुकुमार सेन बंगाली भाषा में रचित अपनी कृति 'रामकथार प्राक्-इतिहास' में लिखते हैं, '' औपचारिक तौर पर हम यह कह देते हैं कि रामायण और महाभारत एक ही दर्जे पर रखे जा सकते हैं क्योंकि हमारे लिए ये समान स्तर के और सम मर्यादा के धर्मग्रंथ हैं। यह बिल्कुल सही नहीं है। हमारी परम्परा भी इस बात को सच नहीं मानती है। रामायण है एक महाकाव्य, कवि द्वारा रची गई रचना जबकि महाभारत है 'इतिहास', पीढ़ी दर पीढ़ी लोक परम्परा से प्राप्त जनश्रुति।... महाकाव्य होने के कारण रामायण रचना की गणना धर्मग्रंथ के रूप में नहीं होती है। लेकिन ऐतिहासिक पुराण के अन्तर्गत आने से महाभारत की मर्यादा व हैसियत धर्मग्रंथ की है। किसी-किसी अनुष्ठान में महाभारत के पाठ का निर्देश स्मृतिशास्त्र में भी दिया गया है।

... महाभारत को 'इतिहास' माना जाता है, लेकिन इस शब्द के हमारे द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले आजकल के मायने में नहीं। अतीत में इस शब्द का मायना था पुरानी कहानियाँ।''

लेकिन इन मतों पर पहुंचने से पहले महान विद्वान इस पुस्तक की प्रस्तावना में लिखते हैं, ''मेरी यह चर्चा इतिहास-निष्ठा की पगडण्डी पर चलती है, धर्मविश्वास के अन्तरिक्ष यान में नहीं उड़ती है, इतिहास-निष्ठ व धर्मविश्वासी की यात्रा भिन्नमुखी होती है। इतिहास के पथ पर अग्रसर होना है तो तथ्य का पाथेय चाहिए, इसे खड़े होने के लिए युक्ति का सहारा चाहिए। प्रमाण में ही इतिहास के प्राण निहित होते हैं जबकि धर्म के प्राण प्रमाण से बाहर होते हैं।'' इतिहास का अध्ययन करने के वैज्ञानिक तरीके के लिए यह स्पष्ट प्रतिपादन खूब पर्याप्त है।

रामानुजम ने इन सब बिन्दुओं, जैसे कि रामायण के विविध संस्करणों, इन सब संस्करणों में पायी जाने वाली विभिन्नताओं व विरोधाभासों और सच्चाई पर पहुंचने के लिए वस्तुवादी, तर्कसंगत खोज पर विस्तार से चर्चा करते हुए इतिहास के अध्ययन के ऐसे वैज्ञानिक तरीके को लेकर स्पष्ट तौर पर प्रयास किये हैं। वे यह मानने के खिलाफ चले जाते हैं कि रामायण एक है, अपूर्व है और पवित्र धर्मग्रंथ है हालाँकि बाद वाले ख्याल को काफी हद तक लोकप्रिय समर्थन प्राप्त है। इस पर यह सवाल उठता है कि ऐसे मुद्दे पर कैसे विचार किया जाये? दिल्ली विश्वविद्यालय ने भारतीय सामाजिक-राजनैतिक घटनाक्रम के इस नाजुक मोड़ पर अचानक रामानुजम का लेख हटाने का फैसला क्यों लिया है जब हर बात में स्वेच्छाचार हावी होता जा रहा लगता है? जीवन की हजारों समस्याओं से पहले ही त्रस्त लोगों को यह मुद्दा कैसे प्रभावित व मदद करता है? क्या इस कार्रवाई का किसी अकेडमिक सवाल से कोई ताल्लुक है? क्या इसका शिक्षा से कोई लेना-देना है? असलियत यह है कि इसी लेख को एक घोर हिन्दू कट्टरतावादी पार्टी बीजेपी की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) द्वारा कुछ अर्सा पहले 2008 में निशाना बनाया गया था। उनका राजनैतिक अस्तित्व इस बात पर और जनता के इस विश्वास को भुनाने पर टिका हुआ है कि राम भगवान थे, रामायण पवित्र ग्रंथ है। चूंकि रामानुजम का लेख असल में इस थीम पर सवालिया निशान लगा देता है इसलिए उनका राजनैतिक अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। इसलिए उन्होंने इसे पाठ्यक्रम से हटाने की माँग उठायी थी। इसके लिए एबीवीपी ने जो रास्ता अपनाया था उसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास के तत्कालीन विभागाध्यक्ष एस. जाफरी के दफ्तर में तोड़-फोड़ करना भी शामिल था। इसके बाद उन्होंने धर्म-विद्वेषी होने के आरोप पर इसे पाठ्यक्रम से हटाने के लिए ज्ञापन दिया था। उनका प्रयास विफल हो जाने पर इस बार बीजेपी के एजेण्डे को सिरे चढ़ाने के लिए अकेडमिक काउन्सिल को मोहरा बनाया गया। है और वह भी किसी चर्चा-बहस के बिना ही, किसी तर्क व कारण के बिना ही। साथ ही दिल्ली और केन्द्र में सत्तारूढ़ पार्टी, कांग्रेस की मौन सहमती के बिना यह कदम नहीं उठाया जा सकता था। यह इस बात को उजागर करता है कि कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष जनवादी सिद्धांतों को बुलंद रखने में कितनी गंभीर है। इसके विपरीत, इससे यह भी साबित होता है कि अपने मतभेदों को लेकर या लोगों के प्रति अपनी चिन्ता को लेकर चाहे कांग्रेस और बीजेपी कितना ही शोर मचाती हों असल में वे इस या उस बिन्दु पर जनजीवन से सम्बन्धित महत्वपूर्ण मुद्दों पर, एक ही नाव पर सवार हैं। इसलिए अगर बीजेपी हिन्दू कार्ड खेलती है तो कांग्रेस जरूरत पड़ने पर जिसे नरम हिन्दुत्व कहा जाता है उस कार्ड को खेलने में उससे पीछे नहीं रहती है। ऐसे समय जब सत्ता में बैठी कांग्रेस लगातार भरभराती जा रही है और घोर एकाधिकारी पूंजीपरस्त नीतियों से भारतीय पूंजीवादी राज्य के बढ़ते जा रहे चौतरफा आर्थिक-सामाजिक-राजनैतिक संकट से अपनी लोकप्रियता तेजी से खोती जा रही है तब बीजेपी अपनी बारी के लिए, सत्ता की कुर्सी के लिए घुड़दौड़ में कांग्रेस को हटाकर उसकी जगह लेने की सम्भावना की भनक पा रही है। इस तरह यह कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ रथ यात्रा का या कभी धर्मान्ध हिन्दुत्व का कार्ड खेलती है, जैसे कि तर्क व चर्चा-बहस को दरकिनार कर उठाये गये दिल्ली विश्वविद्यालय के इस कदम पर खेल रही है। जबकि कांग्रेस पूरी तरह अस्तव्यस्तता की हालत में, इस कदम का बेजा फायदा उठाने को तरजीह देती है ताकि बहुसंख्यक हिन्दू वोट बैंक को अपने पक्ष में जीतने के लिए हिन्दुत्व में इस संलिप्तता से चुनावी फसल काटी व बटोरी जा सके। इन बुर्जुआ राजनैतिक संगठनों के लिए राम या रामायण संसदीय राजनैतिक खेल में फायदा उठाने के साधन हैं और धर्म, धर्मविश्वास और श्रद्धा से इनका कोई लेना-देना नहीं है।

लेकिन इन कदमों को महज संसदीय राजनीति के खेल के रूप में पहचान लेने से ही लोगों को चैन की

(शेष पृष्ठ 4 पर)

दिल्ली वि.वि.....

(पृष्ठ 3 का शेष)

सांस नहीं मिल सकती है। उन्हें इस सवाल का जवाब भी तलाशने की जरूरत है कि वह कौन सी बात है जिससे ये पार्टियाँ या पूंजीवादी व्यवस्था के साथ जुड़े निहित स्वार्थ इन मुद्दों को, खासकर इस घड़ी में कुरेदने लगे हैं। वह इसलिए कि यही वह समय है जब आये दिन हर पल जनजीवन विनाशकारी महंगाई और गहराती जा रही गरीबी, कर्जजाल में फंसे किसानों द्वारा हजारों हजार की संख्या में की जा रही आत्महत्याओं, रोजगार-हानि, वेतन जाम और सर्वोपरि भयावह बेरोजगारी, जो शासन के प्रभारी हैं और समाज के गंदले पानी से अपने लिए जितना ज्यादा हो सके फायदा उठाते हैं खासकर उनमें और राजनैतिक सत्ता, पुलिस-प्रशासन और यहाँ तक कि सेना में भी व्याप्त चौतरफा भ्रष्टाचार, परिसेवाओं, खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली आदि का निजीकरण-व्यापारीकरण जो इनको आम गरीब लोगों की पहुंच से बाहर करता जा रहा है, घोर सांस्कृतिक अध:पतन आदि समस्याओं से ग्रस्त है। ये सब खौफनाक समस्याएं और कुछ नहीं बल्कि घोर पूंजीवादी शोषण, भारतीय पूंजीवादी शासकों द्वारा किये जा रहे भेदभाव, दमन-उत्पीड़न की देन हैं। यह पूंजीवादी-साम्राज्यवादी व्यवस्था अपार वैश्विक मंदी में डूबी हुई है और अपने संकट के सारे बोझ को विशालसंख्यक आम मेहनतकश लोगों के कंधों पर डाल कर खुद को इस संकट से उबारने की कोशिश में है। इसलिए पूंजीवादी शासक, एकाधिकारी पूंजीपति और बुर्जुआ व पैटी बुर्जुआ पार्टियाँ जो सत्ता-सुख के लिए इस व्यवस्था की नग्न रूप में सेवा करती हैं, लोगों द्वारा किये जाने वाले हर प्रतिवाद, आन्दोलन को तहस-नहस कर डालने के लिए न केवल दमन-उत्पीड़न व भेदभाव बढ़ा रही हैं बल्कि लोगों का ज्यादा से ज्यादा खून चूसने, शोषण करने के लिए यह सुनिश्चित करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ती हैं कि शोषण-दमन के खात्मे के लिए बड़े पैमाने पर वर्ग संघर्षों व जन आन्दोलनों को खड़ा करने के लिए लोग साहस, दृढ़निश्चय और वैचारिक स्पष्टता के साथ इस व्यवस्था के खिलाफ एकजुट न हों बल्कि इसकी बजाय उनमें फूट पड़ी रहे और वे अपनी टूटी हुई नैतिक रीढ़, धर्मान्ध मानसिकता व धुंधलाई हुई चिंतनशक्ति के साथ हैवान बन जायें जिनमें किसी भी तरह के प्रतिक्रियावादी सोच-विचार को आसानी से रोपा जा सके। यह फासीवाद के पनपने के लिए और चाहे क्रांतिकारी आन्दोलन हों या जनवादी आन्दोलन, उनके उभरने में अड़चनें पैदा करने के लिए एक उर्वर भूमि है।

रामायण के अध्ययन की तर्कसंगत वैज्ञानिक पद्धति की बात करने वाले रामानुजम के इस निबंध को हटा कर दिल्ली विश्वविद्यालय के स्तर की शिक्षण संस्था ने दरअसल उसी विचार की वकालत की है जो इस महाकाव्य को साफ जाहिर है कि अंधविश्वास व जनविश्वास के आधार पर एक धर्मग्रंथ मानती है। इस कार्रवाई के द्वारा इसने केवल पूंजीपति वर्ग के मंसूबे का ही समर्थन किया है। इस घटना ने साथ ही साथ एक और हालिया मनहूस रुझान को उजागर कर दिया है। यह राम-रामायण-राम मन्दिर के उसी तरह के मुद्दे से सम्बन्धित है जिसने पिछले कुछेक दशकों में कट्टरपंथी धार्मिक उन्माद से देश के सामाजिक-राजनैतिक दृश्य को दूषित कर दिया है। यूपी के अयोधा में बाबरी मस्जिद के 16वीं सदी के एतिहासिक स्मारक स्थल पर राम मन्दिर बनाने के लिए 1986 में आरएसएस-बीजेपी गठजोड़ को शिलान्यास करने देने और फिर ईंट पूजन को राजीव गांधी के नेतृत्व में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा दी गई इजाजत, 1990 में बीजेपी नेता एल के आडवानी द्वारा निकाली गई रथ यात्रा जो जहाँ-जहाँ से गुजरी वहीं अपने पीछे साम्प्रदायिक दंगें करवाती आई, हजारों उन्मत कारसेवकों द्वारा 1992 में किये गये बाबरी मस्जिद के तिरस्करणीय ध्वंस, उनके सर्वोच्च दर्जे के नेताओं द्वारा इस पर की गई करतलध्वनियों और दिये गये प्रोत्साहन, गुजरात की नरेन्द्र मोदी-नीत बीजेपी सरकार और इसी आरएसएस-बीजेपी गठजोड़ द्वारा 2002 में कराये गये गुजरात नरसंहार जिसमें अटल बिहारी बाजपेयी, एल के आडवानी-नीत तत्कालीन केन्द्र सरकार सहित पुलिस-प्रशासन-अफसरशाही का पूरा हाथ रहा है, आजाद भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के एक पर एक किये गये अत्यन्त नृशंस हत्याकाण्डों से यह मुद्दा उछला था। ये सब चालाकी से जनता के अवांछित व अनुचित साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण को लाये हैं।

इससे अल्पसंख्यक समुदायों को बड़ा भारी सदमा पहुँचा है जिससे कि उन्हें बाहर आना है। इसमें पूर्ववर्ती बाबरी मस्जिद की जगह अयोधा की जमीन के मालिकाना हक को लेकर आया इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खण्डपीठ का फैसला भी जुड़ गया। राम मन्दिर के मुद्दे को लेकर घटी बाकी सभी घटनाओं के फलस्वरूप इस फैसले से भी साम्प्रदायिक सुर की भनक आ रही थी क्योंकि यह फैसला न्यायशास्त्र और बुर्जुआ लोकतंत्र के तहत भी दरअसल कभी अमल में लाई बई बुनियादी आचार-संहिताओं व प्रक्रियाओं के बुनियादी दायरे से बाहर चला गया था और साक्ष्यों व तथ्यों पर नहीं बल्कि हिन्दुओं की भावनाओं व धार्मिक विश्वास के मुद्देपर, इस विश्वास पर आश्रित रहा कि यह जगह भगवान राम की जन्म भूमि रही है। दूसरी तरफ, जरा भी निस्पक्षता न बरतते हुए इस फैसले ने दरअसल बाबरी मस्जिद के ध्वंस को कानूनी तौर पर जायज ठहरा दिया था और विवादित सम्पत्ति 1528 में बाबर द्वारा निर्मित की गई थी इस साक्ष्य को सिद्ध करने में नाकाम रहने पर मुस्लिम पक्ष की पार्टी के खिलाफ व्यवस्था दे दी थी। राम मन्दिर से सम्बधित घटनाओं के इस सिलसिले में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया फैसला ताजातरीन है। भले ही ये सब अलग-अलग समय पर घटी थी, लेकिन इन सब घटनाओं ने आरएसएस-बीजेपी गठजोड़ द्वारा समाज को दिये गये घावों पर बार-बार नमक ही छिड़का था, हालाँकि साम्प्रदायिक रूप से आवेशित ध्रुवीकरण लोगों में फूट डाल रहा है और उनके भाईचारे व एकता को तोड़ रहा है।

लेकिन यह सिर्फ बुर्जुआ राजनैतिक पार्टियाँ ही नहीं थी जिन्हें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से साम्प्रदायिकता का राग अलापने की बिना पर कठघरे में खड़ा किया जाना चाहिए बल्कि उस घिनौने खेल में उनका साथ देने वालों में जिन्हें अब तक न्याय के लिए निस्पक्ष संस्था के रूप में पेश किया जाता है वह न्याय पालिका, शासन की कमान थामे हुए पुलिस-प्रशासन-अफसरशाही या देश को शिक्षा देने का जिसे जिम्मा सौंपा हुआ है वे अकेडमिक यानी शैक्षणिक संस्थाएं भी शामिल थी। संगीन साम्प्रदायिक जुर्म करने वाले शातिर मुजरिम बिना कोई सजा पाये खुले घूम रहे हैं। यह एक खुला रहस्य है कि गुजरात प्रशासन गुजरात नरसंहार में सीधे संलिप्त था। कोई भी आदमी, चाहे वह राजनैतिक आदमी हो या अफसरशाही का आदमी हो जिसने भी मोदी सरकार की आलोचना करने या उसके रुख-रवैये के खिलाफ राय जाहिर करने की जुर्रत की, उसे या तो मौत के घाट उतार दिया गया या दण्डात्मक कार्रवाइयाँ झेलनी पड़ी। हाल ही में एक-डेढ़ महीने पहले, गुजरात के नरसंहार के एक महत्वपूर्ण गवाह नदीम सयैद को अहमदाबाद में सरेआम मार डाला गया। जाने माने पत्रकार कुलदीप नैयर ने गत 10 नवम्बर को प्रकाशित दि स्टेट्समैन अखबार में छपे लेख में यह आरोप लगाया था कि दिल्ली में 1984 के सिख हत्याकाण्ड में प्रशासन की संलिप्तता को लेकर एफआईआर सहित तमाम रिकार्ड और सबूत नष्ट किये जा रहे हैं। इसलिए यह शासक पूँजीपति वर्ग की साजिश और कारगुजारी है जो सभी समस्याओं की जड़ है और इस दमनकारी पूँजीवादी शासन के खिलाफ कोई प्रतिवाद, आन्दोलन न हो सके इसलिए लोगों की एकता को तोड़ने की दिशा में यह अपनी स्टेट मशीनरी के हर किसी अंग को इस्तेमाल करने से कभी नहीं चूकता है।

इसलिए रामायण पर रामानुजम के निबंध को हटाने का दिल्ली विश्वविद्यालय का फैसला कोई गैर नुकसानदेह शैक्षणिक मुद्दा नहीं है बल्कि शासक वर्ग के विनाशकारी मन्सूबे का एक अभिन्न अंग है। यह जनवादी सोच-विचार वाले हरेक आदमी के लिए गंभीर अनिष्ट का सूचक है। इस फैसले का दायरा महज किसी किताब या लेख को अवैध ठहरा देने तक ही महदूद नहीं है, सिर्फ इसी पर चिन्ता मिट नहीं जाती है बल्कि चिन्ता तो इससे भी ज्यादा जिस गंभीर मुद्दे को लेकर है वह है अभिव्यक्ति की आजादी, भिन्न मत रखने की आजादी। यह पर्दाफास कर देता है कि लोकतंत्र का लबादा ओढ़ कर चलायी जा रही इस व्यवस्था में यह आजादी असल में किस हद तक सुरक्षित है, इसमें इस आजादी के हनन का कितना खतरा बना हुआ है।

यहाँ यह बात दोहरा दें कि यह नवजागरण काल था जब व्यक्ति-स्वतंत्रता व समानता की बुनियादी धारणाओं के आधार पर अभिव्यक्ति की आजादी का नारा दिया गया था, सामंतवाद और सामंती शासकों के अक्कडपन, अहंकार, असहनशीलता के खिलाफ दार्शनिक सहनशीलता की धारणाएं पेश की गई थी और अंधविश्वास पर आधारित दैवीय व सामंती फरमानों के आगे नतमस्तकता की बजाय समाज में भिन्न मत, यहाँ तक कि विरोधी मतों के भी सहअस्तित्व के विचार व अभ्यास को मान्यता दी गई थी, धर्म में विश्वास रखने वालों और धर्म में विश्वास न रखने वालों, आस्तिकों और नास्तिकों के सहअस्तित्व की धारणएं बुलंद की गई थी। बुर्जुआ लोकतांत्रिक समाज ने यह स्वीकार किया था और इसे बढ़ावा दिया था कि कोई अपनी राय दूसरों पर जबरन थोपेगा नहीं। यह सब औपचारिक व अनौपचारिक तौर पर, कानूनी या परम्परागत तौर पर इस आशय से ग्रहीत भी किया गया था कि यह मानव सभ्यता व समाज को बेरोकटोक, बहुमुखी विकास की ओर ले जाएगा। बुर्जुआ लोकतंत्र इन धारणाओं, विचारों व अभ्यासों पर खड़ा हुआ था और इनसे ही अपनी खुराक जुटाता था।

लेकिन अब भारत में हम बुर्जुआ लोकतंत्र को एक ऐसी अवस्था में पा रहे हैं जिसमें यह एक सड़ी-गली व्यवस्था हो चुकी है, यह अपनी सारी जीवनशक्ति खो बैठा है और इसके विपरीत यह सर्वांगीण सड़-गलन से ग्रस्त है। हालाँकि भारतीय राज्य अभी भी लोकतांत्रिक होने का जोरशोर से दावा करता है, उस दृष्टिबिन्दु से क्या जो साहित्य उनके स्वार्थ व मत के खिलाफ जाता है उसे छात्रों की पहुँच से बाहर कर देने के लिए प्रतिबंधित कर देने का जो लोग दबाव डाल रहे हैं और जो लोग उनकी इस नाजायज माँग को स्वाकार कर रहें हैं, उन दोनों से ही महज नवजात फासीवाद के कदमों की आहट सुनाई नहीं देती है? क्या लोकतंत्र शब्द के सही मायने में यह अभिव्यक्ति की आजादी के बिना फल-फूल सकता है या बरकरार रह सकता है? क्या लोकतंत्र इसे पहले से ही मान कर नहीं चलता है कि मत भिन्न भी हो सकते हैं और अन्तिम रूप में उभर कर आने के लिए गरमागरम बहस भी हो सकती है? क्या विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य और इस बात पर मानवजाति का कोई भी सृजनात्मक संकाय अभिव्यक्ति की आजादी को हर तरह से बढ़ावा दिये बिना, चर्चा-बहस के बिना, विचार-विमर्श के बिना उभर कर आ सकता है और फल-फूल सकता है? क्या लोकतंत्र यह पूर्वशर्त नहीं लगा देता है कि किसी भी मुद्दे, खासकर संवेदनशील व गंभीर मुद्दे पर तब तक सच्चाई पर नहीं पहुँचा जा सकता जब तक कि उस पर किसी को समझा-बुझा कर मनवाने के लिए निश्चय ही किसी तरह से किसी को मजबूर किये बिना वैज्ञानिक जाँच-परख, चर्चा-बहस, विचार-विमर्श न हो? वरना मत का कोई दमन, मत पर लगाई गई कोई भी पाबंदी, जैसा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से रामानुजम का लेख हटाने के मामले में हुआ है, एक उसी तरह की घिनौनी करतूत नहीं हो जाएगी, एक फतवा नहीं हो जाएगा जो तालीबानी या ऐसी ही कोई और खतरनाक ताकत जारी कर देती है। एक बार समाज या सम्बन्धित अथोरिटी अगर ऐसे फतवों के आगे घुटने टेकने शुरू कर दे तो इसका अन्त बाद में फासीवाद लाने के सिवाय और कहाँ होगा? इसलिए, यह बहुत जरूरी है कि इस कार्रवाई का हम डट कर मुकाबला करें और इसे शुरूआत में नाकाम कर दें तथा लोकतंत्र के बचे-खुचे अवशेषों की रक्षा करें जो हमारे देश में प्रचलित पतनशील पूँजीवाद के इस सर्वव्यापी संकट की काली छाया व अंधकार में भी अभी बरकरार हैं। ❑❑

ईरान .....

(पृष्ठ 1 का शेष)

तमाम अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए और जनतन्त्र के बचे-खुचे अवशेषों को पैरों तले रौंदते हुए सार्वभौम स्वतन्त्र इराक को सामरिक तौर पर परास्त करके अमेरिका व उसके सहयोगियों ने उस देश में तेल व्यापार पर पुनः नियन्त्रण हासिल कर लिया है, जो 2002 में सद्दाम हुसैन द्वारा अमेरिकी साम्राज्यवाद-विरोधी दृढ़ रुख अपनाने की वजह से उनके हाथ से निकल जाने वाला था। सार्वभौम इराक पर गैर कानूनी कब्जा करने के बाद अमेरिकी साम्राज्यवादी एक के बाद दूसरे पश्चिम एशियाई देशों के तेल क्षेत्रों पर कब्जा जमाने के लिए आतुर थे। लेकिन जब ईरान ने अमेरिकी फरमान के सामने झुकने से मना कर दिया तो उनकी खीज बहुत बढ़ गई।

अमेरिकी साम्राज्यवादियों को उम्मीद थी कि हाल ही में ईरान में सम्पन्न हुए चुनावों में सत्ताधारी शासकों को विपक्ष हरा देगा जिसे उनका भरपूर समर्थन प्राप्त है। लेकिन अमेरिकी शासकों को भारी निराशा हाथ लगी क्योंकि सत्ताधारी शासक पुनः सत्तासीन हो गए और इस तरह ईरान में एक ताबेदार शासन कायम करने की उनकी कोशिश नाकाम साबित हो गई। तब से अमेरिकी साम्राज्यवादियों ने अपने हमलावर तेवर और कड़े कर लिए हैं और पर्दे के पीछे रह कर ईरान के अन्दर अशांति फैलाने के लिए मेहनतकश लोगों के एक तबके को दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की साजिश रच रहे हैं और आपसी संघर्षों को उकसा रहे हैं ताकि वे मानवाधिकारों का उल्लंघन रोकने, आतंकवाद का दमन करने और जनतंत्र को ध्वस्त होने से बचाने के बहाने उस देश के अन्दरूनी मामलों में दखल दे सकें, जिसके चलते ईरान के लोगों को 'जनतन्त्र का तोहफा' देने के लिए धीरे-धीरे पूर्ण सैनिक हमले की तरफ आगे बढ़ा जा सके। अन्तर्राष्ट्रीय गुण्डागर्दी का यही वह खाका है जिसे अमेरिकी नेताओं ने अपने घृणित वर्गस्वार्थ को आगे बढ़ाने के लिए तैयार किया है। इस बात का जिक्र करना भी निहायत जरूरी है कि अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने स्वेच्छाचारी ढंग से घोषणा की है कि पश्चिम एशिया में अमेरिका ''आतंकवाद का मुकाबला करने व आणविक हथियारों का प्रसार रोकने; व्यापार की अबाध गति सुनिश्चित करने; इस क्षेत्र की सुरक्षा करने, इज़राइल की सुरक्षा के लिए समर्थन करने और अरब-इज़राइल शांति के लिए प्रयास करने'' जैसे अपने ''महत्वपूर्ण स्वार्थों'' को पूरा करने के अपने प्रयास जारी रखेगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण स्वार्थ है तेल, जिसके लिए अमेरिका ने पहले ही इस क्षेत्र में दो आक्रामक युद्ध छेड़े थे, उसका उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया और चालाकी से उसे छिपा लिया। अमेरिकी साम्राज्यवादियों व उनके सहयोगियों ने यह भी कहा है कि वे ईरान पर नए प्रतिबंध व तेल व्यापारबंध लगाने पर काम कर रहे हैं।

विशाल तेल भण्डारों को हड़पने के अलावा दूसरे कारण भी हैं जिनके लिए अमेरिकी शासक ईरान व अन्य पश्चिम एशियाई देशों के खिलाफ युद्ध खेलों, दिमागी खेलों, षड्यन्त्रकारी खेलों और जासूसी खेलों का सिलसिला चला रहे हैं। पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की महामारी असमाधेय घोर बाजार संकट से किसी तरह निजात पाने के लिए अमेरिकी साम्राज्यवादी और इस मामले में छोटी-बड़ी सभी साम्राज्यवादी ताकतें उद्योगों के अंधाधुंध पुनरस्त्रीकरण-सैन्यीकरण का सहारा लेने को मजबूर हैं ताकि धसकती जा रही अर्थव्यवस्था को कुछ हद तक कृत्रिम उत्तेजना, बढ़ी हुई मिलिट्री खपत के जरिए प्रदान की जा सके। जितना ज्यादा अर्थव्यवस्था का सैन्यीकरण होता जा रहा है उतनी ही उग्रता से अमेरिकी साम्राज्यवादियों के नेतृत्व में विश्व साम्राज्यवाद दूसरों पर युद्ध थोपता जा रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण आर्थिक पहलू यह है कि अमेरिकी डॉलर जैसा कि हम जानते हैं हर तेल आयात करने वाले देश के लिए जरूरी है। यही वजह है कि इनमें बहुत से देशों के केन्द्रीय बैंक अपने विदेशी मुद्रा भण्डार को डॉलरों में रखते हैं। इस तरह ज्यादा डॉलर अमेरिका के बाहर चलन में हैं या विदेशी मालिकों द्वारा अमेरिकी परिसंपत्तियों में निवेश किए हुए हैं। नतीजतन, बाकी दुनिया को इन डॉलरों के बदले में अधिक सामान और सेवाएं अमेरिका को प्रदान करनी पड़ती हैं। अन्य देशों को अमेरिका अपना कर्ज सिर्फ अपनी मुद्रा छाप कर अदा कर सकता है। जब कुछ महत्वपूर्ण तेल उत्पादक देशों ने तेल व गैस क्षेत्र में व्यापार के लिए डॉलर के बदले यूरो में लेनदेन शुरू कर दिया तब डॉलर का यह अति विशिष्ट दर्जा खतरे में पड़ गया। हमले का शिकार होने से ठीक पहले इराक ने भी यही करना चाहा था। लेकिन ईरान अपने एनर्जी रिवेन्यू के लिए अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता से बाहर आने का तब साहस कर सका था जब इसे 2006 में प्रतिबन्धों का सामना करना पड़ा था और इस प्रकार विश्व बाजार में अमेरिकी डॉलर की माँग काफी हद तक घट गई थी। अमेरिकी साम्राज्यवादियों को डर है कि कहीं दूसरे तेल निर्यातक देश भी इसका अनुसरण करने लगे तो उनके लिए इसके भयंकर परिणाम होंगे।

इन निहित आर्थिक स्वार्थों के अलावा अन्य मुख्य राजनीतिक कारण भी है। जहाँ पश्चिम एशिया के अनेक शासकों ने अमेरिकी साम्राज्यवाद के सामने न चाहते हुए भी आत्म समर्पण स्वीकार कर लिया है और पैण्टागन शासन के पिछलग्गू बन गए हैं, वहीं पश्चिम एशिया के विभिन्न भागों में अमेरिकी प्रभुत्व व दबदबे के खिलाफ उठ रहे प्रतिरोध आन्दोलनों को ईरान के साथ-साथ सीरिया व लेबनान की सरकारों से हर तरह का समर्थन व प्रोत्साहन मिल रहा है। यहाँ तक कि लेबनान ने सफलतापूर्वक अमेरिका द्वारा प्रायोजित फौजी हमले को भी पीछे धकेल दिया है। इस महत्वपूर्ण पश्चिम एशियाई जोन में यह बढ़ता प्रतिरोध फिलस्तीनियों के मुक्ति संघर्ष को मदद व मजबूती दे रहा है, जिससे इज़राइल के उग्र यहूदीवादी (जियोनिस्ट) शासक बहुत परेशानी महसूस कर रहे हैं। सीरिया व लेबनान के मुकाबले ईरान के पास श्रेष्ठ मिलिट्री ताकत है, यह समृद्ध तेल भण्डारों से भरपूर है और इसकी भौगोलिक स्थिति का सामरिक महत्व है। ईरान को अस्थिर कर देने से अमेरिकी शासकों के लिए न केवल इसके तेल भण्डारों पर कब्जा करना आसान हो जाएगा बल्कि यह इस पूरे क्षेत्र में इसके आधिपत्य को सुदृढ़ बनाने में भी इसका मददगार होगा और साथ ही साथ जोर पकड़ रहे अमेरिका-विरोधी प्रतिरोध आन्दालनों पर भी नैतिक प्रहार करेगा। इसलिए, ईरान अब अमेरिकी साम्राज्यवादियों के मुख्य निशाने पर है और इज़राइल ताक में बैठा है कि ज्योंही बड़े भाई से इशारा मिले वह ईरान पर हमला कर दे।

ईरान के खिलाफ अमेरिका साजिश रच रहा है

शैतान के पास तिकड़मों की कोई कमी नहीं होती है। स्मरणीय है कि अमेरिकी शासकों द्वारा इराक पर आरोप लगाया गया था कि इसके पास जनसंहारक हथियार हैं, बाद में जिनके बारे में साबित हो गया कि यह सब झूठ था। ईरान के मामले में तेहरान के आणविक उर्जा कार्यक्रम को निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिकी साम्राज्यवादियों द्वारा तर्क पेश किया जा रहा है कि चूँकि ईरान उर्जा संसाधनों का धनी है इसलिए इसको आणविक उर्जा पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है, तेहरान के आणविक उर्जा कार्यक्रम के बारे में उनका मानना है कि यह परमाणु बम रखने वाला देश बनने के अन्तिम लक्ष्य पर पहुँचने के लिए तेहरान का पहला कदम है।

उनका ईरान पर यह आरोप भी है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद की मदद कर रहा है और तोड़फोड़ की कार्रवाइयों को पनाह दे रहा है। ईरान ने साफ तौर पर दो टूक शब्दों में अमेरिकी अधिकारियों द्वारा लगाए इस नितांत झूठे आरोप की निन्दा की है और आक्रमणकारी युद्ध छेड़ने से पहले बाँह मरोड़ने के पेण्टागन शासन के घिनौने मकसद को छिपाए रखने का एक मनहूस बहाना बताया है। जहाँ अमेरिकी शासक ईरान के एक न्युक्लियर ताकत बनने की संभावना पर इतना शोर मचा रहे हैं वहीं सच्चाई यह है कि उग्र यहूदीवादी (जियोनिस्ट) इज़राइल एक आणविक शक्ति है जिसके पास लगभग 300 आणविक आयुद्ध हैं। स्पष्ट तौर से अमेरिकी शासकों के आदेश पर इज़राइल ने फिलस्तीनी मुक्ति योद्धाओं के खिलाफ घोर अन्यायपूर्ण युद्ध छेड़ रखा है, बार-बार पड़ोसी सीरिया, लेबनान व अन्य देशों पर आक्रमण किया है और गोलान हाइट्स क्षेत्र में वहशीपन का नंगा नाच किया है। इज़राइल ने पहले ही ईरान के खिलाफ सशस्त्र झड़पें शुरू कर दी हैं। ईरानी सिस्टमों को पंगु बनाने के लिए 'आश्चर्यजनक रूप से सटीक' स्टुक्सनेट जीवाणु या डुक्यु विषाणु के इस्तेमाल की चर्चा भी विभिन्न हलकों में हो रही है। एक ईरानी मिसाइल बेस में 12 नवम्बर को हुए धमाके में भी इज़राइली गुप्तचर विभाग का हाथ होने का संदेह जताया जा रहा है। सिर से लेकर पांव तक हथियारों से लैस और पेण्टागन से शह पाये हुआ इज़राइल, ईरान सहित पश्चिम एशिया में तमाम देशों के लिए खतरा बना हुआ है। इज़राइल व अमेरिका नियमित रूप से ईरान के आस पास के क्षेत्रों में सैनिक अभ्यास कर रहे हैं, विभिन्न पश्चिम एशियाई क्षेत्रों में अपने वायुसैनिक व नौसैनिक अड्डों को मजबूत कर रहे हैं और अपने आणविक आयुद्धों से भरे शस्त्रागार को बढ़ाते जा रहे हैं। यही हैं जो इराक पर गैर-कानूनी कब्जे के बाद इस क्षेत्र में नए सिरे से युद्ध तनाव बढ़ा रहे हैं और जिन्होंने लिबिया में तख्तापलट कराया। ईरान को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। लेकिन ध्यान बटाने के लिए पेण्टागन शासक ईरान पर आरोप लगा रहे हैं कि अपनी आणविक क्षमताओं को विकसित करके वह शांति को खतरे में डाल रहा है। ईरान द्वारा अपनी आणविक क्षमताएं बढ़ाये जाने के मुद्दे को इस पृष्ठभूमि में देखना चाहिए जिसमें अमेरिकी साम्राज्यवादियों व उसके सहयोगियों ने उस सार्वभौम स्वतन्त्र देश को पूरी तरह दीवार से सटा दिया है।

प्रत्येक देश को अपनी रक्षा का अधिकार है

ईरान ने बार-बार कहा है कि केवल शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए ही वह आणविक क्षमता हासिल करना चाहता है। जबकि अगर मर्यादा व निष्पक्षता बरकरार रखी जाए तो वह अमेरिकी साम्राज्यवादी हुकूमत या उसके चेले इज़राइल समेत किसी के भी साथ और किसी भी मुद्दे पर बैठने और बात करने के लिए तैयार है। ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर कोई अक्खड़पन से और खंजर लहराते हुए धमकी भरे लहजे में बात करना चाहता है तो जिसमें जरा भी आत्मसम्मान बाकी है वह कोई भी स्वतन्त्र सार्वभौम देश इसे स्वीकार नहीं करेगा। साफ बात है कि अगर इस तरह लगातार बांह मरोड़ी जाती हो और किसी भी समय हमला हो जाने की तलवार लटक रही हो तब कोई देश आत्मरक्षा के लिए अपनी क्षमताओं को बढ़ाता है तो किस आधार पर उसे गलत या नाजायज कहा जा सकता है? अमेरिकी साम्राज्यवादियों द्वारा जिन देशों को ''बुरे'' या ''दुश्मन राज्यों'' के रूप में पेश किया जा रहा है क्या इनमें से किसी ने किसी दूसरे देश के खिलाफ कभी कोई आणविक हथियार या जनसंहारक हथियार इस्तेमाल किया है, सैनिक हमला किया है और दूसरों के क्षेत्रों पर कब्जा किया है, विदेशी क्षेत्रों पर आक्रमण करने के लिए विदेशी जमीनों पर असंख्य सैनिक अड्डों की स्थापना की है, दूसरे देशों के समुद्री तटों के साथ-साथ गश्त लगाने के लिए घातक आणविक हथियारों से लैस नौसेना को भेजा है, किसी सार्वभौम देश की हवाई सीमा का उल्लंघन किया है, मानवरहित ड्रोन हेलीकोप्टरों से दूसरे देशों के सीमाक्षेत्रों में हवाई हमले करके बम बरसाए हैं, उनके आदेशों को न मानने की जुर्रत करने पर उन्होंने दूसरे देशों को सशस्त्र हमलों, स्टार युद्धों व आणविक युद्धों की धमकी दी है या दूसरे देशों की एकता व आजादी को पैरों तले रौंदा है? अमेरिकी साम्राज्यवादियों के नेतृत्व में ये विकसित साम्राज्यवादी-पूँजीवादी देश ही हैं जो अपने बाजार विस्तारित करने, प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने और सुपर पॉवर के रूप में उभरने की निहित वर्ग जरूरतों से संचालित होकर आणविक हथियार विकसित करने के अपने प्रयास और 19वीं सदी के मध्य से ही न्युक्लियर

(शेष पृष्ठ 6 पर)

ईरान .....

(पृष्ठ 5 का शेष)

ब्लैकमेलिंग की अपनी मनहूस राजनीति तेज करने में लगे हुए हैं। सरकारी हिसाब से अमेरिका ने अब तक 1,054 परमाणु परीक्षण किये हैं जिनकी संख्या अन्य देशों द्वारा किए गए ऐसे परीक्षणों की कुल संख्या से कहीं ज्यादा है। अमेरिकी साम्राज्यवादियों द्वारा ही सबसे पहले एटम बम बनाया गया था। अपनी मिलिट्री श्रेष्ठता का प्रदर्शन करने के लिए न्युक्लियर बम गिराया था और दुनिया में दहशत और तबाही, नरसंहार और सर्वनाश का दौर ला दिया था। वे अपने आणविक शस्त्रागार लगातार बढ़ाते जा रहे हैं और नये-नये जन संहारक हथियार इजाद करते जा रहे हैं। उनके द्वारा नापाम बम, एजेंट-ओरेंज जैसे घातक हथियारों का इस्तेमाल वियतनाम व इराक में खुलकर किया गया जिससे लाखों बेगुनाह लोग मारे गए और रेडियाधर्मी किरणों से पैदा होने वाली बीमारियों से लाखों लोग विकलांग हो गए। उग्र यहूदीवादी (जियोनिस्ट) इज़राइल द्वारा फिलीस्तीन पर इसी तरह के हथियारों का इस्तेमाल किए जाने के पुख्ता सबूत मिले हैं। प्रत्येक तथ्य यही सिद्ध करता है कि अमेरिकी साम्राज्यवादियों व उनके सहयोगियों ने तय कर लिया है कि आणविक हथियारों रखने का हक सिर्फ उन्हीं तक महदूद रहेगा जबकि दूसरों को इस क्षेत्र में कदम रखने की मनाही है।

इस संदर्भ में यह भी बता देना जरूरी है कि अमेरिकी साम्राज्यवादियों द्वारा एटम बम गिराकर जब हीरोशिमा व नागासाकी शहरों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया था तब विश्व जनमत इस बात के हक में था कि सिर्फ आणविक हथियारों का ही नहीं बल्कि हर तरह के हथियारों का पूर्ण खात्मा किया जाना चाहिए। धरती को युद्ध की तबाही से मुक्त करने के लिए, स्टालिन के नेतृत्व में तत्कालीन सशक्त समाजवादी खेमे ने पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण समेत मुकम्मल और चौतरफा निरस्त्रीकरण का आह्वान किया था। लेकिन अमेरिकी साम्राज्यवाद के नेतृत्व में साम्राज्यवादी खेमे ने इस विश्व जनमत पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि इसकी बजाए वे और भी ज्यादा परिष्कृत परमाणु हथियार विकसित करने में लिप्त रहे और सहायता प्रदान करने की आड़ में ताक-झांक करने, राजनीतिक हत्याएं करवाने, तख्तापलट करवाने का षड़यन्त्र रचने, आंशिक व स्थानीय युद्धों को भड़काने और युद्धातंक व तनाव को हवा देने आदि हर तरह की दुष्टतापूर्ण कार्रवाइयों में लगे रहे। इस तरह जब स्थाई शांति के लिए दुनिया की जनता द्वारा पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण समेत मुकम्मल चौतरफा निरस्त्रीकरण की जायज माँग की जा रही थी तब ये अमेरिकी साम्राज्यवादी और उनके चेले चांटे ही थे जो विश्व जनमत की पूर्ण अवहेलना करते हुए तनाव और वैमनस्य बढ़ाने के लिए घातक आणविक हथियारों के उत्पादन में तीव्रता लाते रहे और इस जघन्य एजेंडे को छिपाये रखने के लिए पेंटागन शासकों ने तथाकथित परमाणु प्रसार की धारणा फैला दी और परमाणु-अप्रसार संधि को मानने के लिए दूसरे देशों पर दबाव डालने लगे जबकि परिष्कृत आणविक हथियारों के उत्पादन के अपने अधिकार को बरकरार रखे रहे ताकि दूसरे राष्ट्रों को अपने निरन्तर आधिपत्य में रखा जा सके। कल को वे ऐसी घोषणा भी कर सकते हैं कि गैर-आणविक हथियारों के उत्पादन पर उनका विशेषाधिकार है और दूसरे देश ऐसा करने से बाज आयें। अगर इस अमेरिकी धोंसपट्टी को चुनौती नहीं दी गई तो ऐसी संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

अत: कहने की कोई खास जरूरत नहीं है कि नवीनतम आणविक आयुद्धों से लैस अमेरिकी लुटेरों की डाकेजनी युद्ध की संभावनाओं को बढ़ा रही है, विश्व वातावरण को तनावपूर्ण बना रही है और दहशत की काली छाया को बढ़ा रही है। अमेरिकी साम्राज्यवादियों के नेतृत्व में 11 देशों के साम्राज्यवादियों की अन्तर्राष्ट्रीय स्वेच्छाचारिता और डाकेजनी ही आणविक प्रसार का मूल कारण है। अत्याधुनिक आणविक हथियारों और जनसंहार के आधुनिक परिष्कृत अस्त्र-शस्त्रों से लैस अमेरिका ही आज दुनिया में सबसे बड़ा आतंकवादी राष्ट्र है। आणविक श्रेष्ठता ही अमेरिकी साम्राज्यवादियों में यह अक्खड़पन पैदा कर रही है जिसके चलते वे छुट्टे साण्ड की तरह सींग मारते फिर रहे हैं, दूसरों को धमका रहे हैं और जब चाहें हत्याकाण्ड और कोहराम मचा रहे हैं। यह अमेरिकी साम्राज्यवादी स्टेट ही है जो आज विश्व शांति, सभ्यता व मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अमेरिकी साम्राज्यवाद को क्या हक है कि वह दूसरों को आणविक क्षमताएं विकसित करने से मना करे, जब वह खुद हरदम अपनी आणविक शक्ति में इजाफा कर रहा है? अमेरिकी साम्राज्यवादियों के तमाम आणविक शस्त्र भण्डार को तुरन्त नेस्तानाबूद करने की फौरी जरूरत पर विश्व जनमत को एकजुट करने की जरूरत है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक अपने वजूद को कायम रखने और अपनी सार्वभौमता व स्वतन्त्रता की हिफाजत करने के अनुलंघनीय अधिकार की रक्षा की खातिर हर देश के लिए हर पहलू से यह न्यायसंगत है कि वह अगर जरूरत पड़े तो आणविक शक्ति हासिल करे और उसे निरन्तर विकसित कर सके। यह नहीं हो सकता कि जिनके पास आणविक दाँत हैं वे तो आणविक ताकत विकसित करने के बेरोकटोक अधिकारी बने रहें जबकि दूसरों को उनकी क्रोधित आँखों के सामने दब्बू बनकर घुटने टेकने पड़ें और अपने आणविक कार्यक्रम छोड़ देने पड़ें या तबाही झेलनी पड़े। दो धड़ों के लिए दो अलग-अलग पैमाने नहीं हो सकते हैं। अगर आणविक हथियारों पर रोक लगे तो यह सब पर समान रूप से लागू हो। जिनके पास आणविक शक्ति है और जिनके पास नहीं है उनके बीच ध्रुवीकरण न हो। अमेरिकी साम्राज्यवादी जिन्होंने झूठे बहाने की आड़ में विध्वंसात्मक उद्देश्य के लिए पहले आणविक युद्ध शुरू कर दिया था उन्हें हर किसी के सर पर सवार होने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ऐसी पृष्ठभूमि में, ईरान जैसे देशों के पास क्या विकल्प बचा है जिन पर अमेरिकी साम्राज्यवादियों द्वारा हमला किए जाने का खतरा हमेशा मण्डराता रहता है, सिवाए इसके कि वे आत्म-रक्षा के लिए आणविक हथियार विकसित करने का सहारा लें? इन देशों द्वारा उठाए जाने वाले ऐसे कदमों को कैसे गैर कानूनी करार दिया जा सकता है क्योंकि हरेक देश का यह जन्मजात अधिकार है कि वह अपनी सार्वभौमता व स्वतन्त्रता की रक्षा चाहे जिस भी तरीके से करे, जिसे वह सही और उपयुक्त मानता हो, चाहे इसका मायना खुद की आणविक क्षमताएं विकसित करना ही क्यों न हो? इन हालात में इस बात को समझना लाजिमी है कि दुनिया को आणविक हथियारों से मुक्त करने के लिए विश्वव्यापी जोरदार जनआन्दोलन मजबूत करना निहायत जरूरी है। इस आन्दोलन के दबाव से ही अमेरिकी साम्राज्यवादियों को न्युक्लियर हथियारों के खात्मे सहित पूर्ण निरस्त्रीकरण के लिए सहमत होने के लिए मजबूर किया जा सकता है ।

शासन के तौर तरीके बदलने का फैसला उस देश के लोग ही करेंगे

इस सम्बन्ध में यह बताना निहायत जरूरी है कि अमेरिकी साम्राज्यवादी अब नग्न रूप से दूसरे देशों के अन्दरूनी मामलों में सैनिक तौर पर भी दखल दे रहे हैं, अपने-अपने देश के शासकों के दमन-उत्पीड़न से नागरिकों की रक्षा करने के नाम पर 'मानवतावादी' मिशन की आड़ ली जाती है। यह सच है कि पूँजीवादी और सामंती-पूँजीवादी देशों में वहाँ का शासक वर्ग बुर्जुआ शासन को सुदृढ़ बनाने के लिए लोगों की जनवादी आकांक्षाओं का दमन करता है और अक्सर दमनात्मक रास्ता भी अपनाता है। वहाँ इसके खिलाफ बढ़ता हुआ जनाक्रोश भी है जो अक्सर प्रतिवाद की शक्ल में फूट पड़ता है। हाल ही में, उत्तरी अफ्रीका और मध्य-पूर्व के अनेक देशों में लोगों का रोष फूट पड़ा है और वहाँ की जनता अपने निरंकुश शासकों के खिलाफ जुझारू जनउभार में सड़कों पर आ गई है। अगर वहाँ के शासक या तो अमेरिकी साम्राज्यवादियों के ताबेदार या उनके साथ मिलीभगत करने वाले रहे तो पेण्टागन शासकों ने उनका साथ दिया और इन शासकों द्वारा उठाए गए तमाम जनविरोधी कदमों का बेशर्मी से समर्थन किया जैसा कि हाल ही में बहरीन, सऊदी अरब, यमन, जोर्डन, कतर और ओमान में देखा गया। यहाँ तक कि ओबामा प्रशासन ने सऊदी अरब को सलाह दी कि वह बहरीन के बादशाह के खिलाफ डेमोक्रेसी आन्दोलन को कुचलने के लिए 2000 से अधिक सैनिक व युद्ध के दूसरे साजोसामान भेजे। लेकिन जिन देशों की सरकारें अगर अमेरिकी साम्राज्यवाद की विरोधी हों तो पेंटागन शासक दूसरा रणकौशल अपनाते हैं। तब वे आन्दोलनकारी लोगों की सत्ता-विरोधी भावना को परोक्ष रूप से भड़काते हैं, डेमोक्रेसी को परवान चढ़ाने या लोगों की जायज मांगों को हासिल कराने के लिए नहीं बल्कि इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि उनके प्लाण्ट किये हुए एजेंट या उनसे सहायता प्राप्त असंतुष्ट गिरोह और ताकतें जनता को गुमराह कर सकें और जनसंघर्ष की परिणति उनकी ताबेदार हुकूमतों को सत्ता में बिठाने और इस तरह उनका अपना आधिपत्य कायम करने में की जा सके। ठीक ऐसा ही इराक, मिस्र और लीबिया में हुआ है। इस सम्बन्ध में यह समझना महत्वपूर्ण है कि अगर किसी देश का कोई शासक वहाँ लोगों का दमन-उत्पीड़न करता है, मानवाधिकारों का हनन करता है, लोकतंत्र को खत्म करता है या प्रतिरोध की आवाज को दबाता है तो मौजूदा सत्ताधारियों को सत्ता में बने रहने दें या शासन तन्त्र में परिवर्तन लाएं – यह फैसला करने का पूर्णत: विशेषाधिकार उस देश की पीड़ित जनता का है। सभ्य समाज के किसी चार्टर या कन्वेंशन द्वारा बाहर की किसी हुकूमत को यह अख्तियार नहीं दिया गया है कि वह किसी बहाने या किसी किस्म की तिकड़म की आड़ में उस देश के अन्दरूनी मामलों में दखल दे। अगर किसी देश के लोग अपने स्वेच्छाचारी दमनकारी शासकों के खिलाफ न्यायसंगत संघर्ष करने में लगे हुए हैं तो दूसरे देशों के मेहनतकश लोग या शासक भी उनके साथ अपनी एकजुटता का इजहार कर सकते हैं, उन्हें नैतिक समर्थन दे सकते हैं और उनके संघर्ष के पक्ष में जन समर्थन जुटा सकते हैं। लेकिन फौजी दखलअंदाजी की बात तो दूर रही किसी तरह की दखलअंदाजी की कोई इजाजत नहीं है। तब यह जनवादी तौर तरीकों, नैतिकता और रवायतों, अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीतिक विधि-विधानों और कन्वेंशनों का सरासर उल्लंघन होगा। कोई देश जो इन स्थापित सिद्धान्तों का उल्लंघन करता है, किसी अन्य स्वतन्त्र देश की स्वायत्तता का अतिक्रमण करता है और वह भी दस्युगिरी और जलदस्युगिरी के घृणित उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए करता है तो उसे मानवता के खिलाफ बर्बरतापूर्ण अपराध करने का दोषी माना जाएगा। अमेरिकी साम्राज्यवादी युद्धखोर और उनके सहयोगी अपनी भरी तिजोरियों को और भी ठूंस-ठूंस कर भरने के लिए जानबूझ कर इस अपराध को अंजाम दे रहे हैं। युगोस्लाविया, अफगानिस्तान, इराक व लिबिया की घटनाओं में लेनिन की इस थीसिस की सच्चाई साफ जाहिर हो गई है कि साम्राज्यवाद युद्धों का जन्मदाता है और विश्वशांति के लिए मुख्य खतरा है। अब, ईरान की बारी है। आज कोई भी देश सुरक्षित नहीं है। अमेरिकी साम्राज्यवादियों व उनके सहयोगियों का खूनी पंजा किसी भी समय किसी भी देश पर झपट सकता है, ''घुटने टेक दो या तबाह हो जाओ''–अमेरिकी साम्राज्यावादियों का यही फरमान है।

साम्राज्यावादियों के इस मनहूस षड़यन्त्र को परास्त करो

क्या हर देश को इस धमकी के सामने घुटने टेक देने चाहिए? क्या अगर उनके अपने-अपने देश के शासक इस प्रकार के आपराधिक क्रियाकलापों के प्रति कायरतापूर्ण समर्पण कर देते हैं तो दुनिया के मेहनतकश लोगों को चुप रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं। यह खूनी खेल बन्द होना चाहिए। भले ही अमेरिकी नेतृत्व में साम्राज्यवादी ताकतें आधुनिक घातक हथियारों से लैस हों लेकिन दुनिया के लोग भी कतई लाचार नहीं हैं। अपनी सार्वभौमता को बचाने और अपनी खुद की रक्षा करने का कम से कम एक हथियार तो उनके हाथों में है वह है, उनकी अपराजेय वैचारिक शक्ति। इसको आधार बनाकर दुनिया भर में व्यापक आधार वाले

(शेष पृष्ठ 7 पर)

ईरान .....

(पृष्ठ 6 का शेष)

सशक्त सुसंगठित साम्राज्यवाद-विराधी आन्दोलन विकसित करने की जरूरत है, जिनमें हर तबके के मेहनतकशों और जनवादी सोच रखने वाले देशभक्त लोगों को शामिल कराया जाए तथा सच्चे कम्युनिस्ट धुरी के तौर पर इनके केन्द्र में रहें। यह निश्चित रूप से लोगों की खुद की राजनीतिक शक्ति को जन्म देगा। अत:, विभिन्न देशों में साम्राज्यवाद-विरोधी आन्दोलनों को ठीक तरह से समन्वित करने की जरूरत है ताकि साम्राज्यवाद, खासकर अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ एक जोरदार जुझारू वैश्विक जन आन्दोलन दुनिया भर में विकसित किया जा सके और इस आन्दोलन की जबरदस्त ताकत को लोगों की निर्णायक राजनीतिक शक्ति में तब्दील कर दिया जाए। अगर ऐसा आन्दोलन सही क्रान्तिकारी विचारधारा के आधार पर विकसित होता है तो यह तकलीफज़दा लोगों के हाथों में एक अभेद्य हथियार होगा जिससे वे युद्धखोर अमेरिकी साम्राज्यवाद को रोक सकते हैं और दूसरों पर हावी होने के उनके तमाम मनहूस षड़यन्त्रों को परास्त कर सकते हैं। इसके साथ-साथ विभिन्न देशों में जनसंघर्ष कमेटियों के निर्माण और निचले स्तर से स्वयंसेवक वाहिनियों के गठन के जरिये सही क्रान्तिकारी नेतृत्व के तहत अपने-अपने देश के उत्पीड़क बुर्जुआ शासकों के खिलाफ दीर्घस्थाई न्यायसंगत जनवादी आन्दोलन संगठित किये जाने निहायत जरूरी हैं। इसके लिए जरूरी है कि साम्राज्यवाद-विरोधी आन्दोलन विकसित करने की इतिहास द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी निभाने के लिए मेहनतकश लोग आगे आएं।

इस बात को भी समझना अति महत्वपूर्ण है कि आज पूँजीवाद-विरोधी क्रान्तिकारी आन्दोलन में सहायक हुए बिना कोई भी जनसंघर्ष अपनी तार्किक परिणति पर नहीं पहुँच सकता है। संशोधनवादी षड़यंत्र के फलस्वरूप विश्व साम्यवादी आन्दोलन के कमजोर हो जाने की वजह से ही साम्राज्यवादी भेड़ियों को मनमानी हत्याएं और मजे से लूटमार करने का लाइसेंस मिल गया है। यह याद रखना जरूरी है कि दूसरे विश्वयुद्ध के बाद अमेरिका ने अति शक्तिशाली युरोपीय साम्राज्यवादी ताकतों पर वस्तुत: अपना आधिपत्य कायम कर लिया है। लेकिन उस समय अमेरिकी साम्राज्यवादियों ने जब भी किसी दूसरे देश पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया या दूसरों के अन्दरूनी मामलों में दखलअंदाजी करनी चाही तो उन्हें कड़े विरोध और शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। क्योंकि उस समय अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी आन्दोलन अपने चरम उत्कर्ष पर था। स्टालिन के नेतृत्व में सोवियत यूनियन सशक्त समाजवादी खेमे का सिरमौर था जिसे शांति का गढ़ माना जाता था। माओ त्से-तुंग ने अमेरिकी साम्राज्यवादियों द्वारा सीधे-सीधे समर्थित कठपुतली च्यांग काइ शेख हुकूमत को करारी शिकस्त देते हुए चीन में क्रान्ति की थी। आक्रमणकारी पेण्टागन सेना जिसे पहले कोरियाई युद्ध में परास्त किया गया था, उसके खिलाफ वियतनामी लोगों के ऐतिहासिक संघर्ष का नेतृत्व हो ची मिन्ह ने किया था। दुनिया भर में साम्राज्यवाद-विरोधी जुझारू शांति आन्दोलनों, उपनिवेशवाद-विरोधी मुक्तिसंघर्षों की बाढ़ सी आ गई थी। यहाँ तक कि बर्नार्ड शॉ, आइन्स्टीन और बर्टण्ड रसल जैसे मानवतावादी शख्स भी मुक्ति संघर्षों के समर्थन में डटकर खड़े हो गये थे और अमेरिकी साम्राज्यवाद-नीत साम्राज्यवादी ताकतों द्वारा लोकतंत्र को कुचलने के सभी प्रयासों के विरोध में खड़े हो गए थे। इस तरह की विश्व परिस्थिति में अमेरिकी साम्राज्यवादी पूरी तरह कोने में धकेल दिए गए थे और उन्हें अपने मनहूस एजेण्डे को छोड़ने को मजबूर होना पड़ा था। मानव सभ्यता की इस संकट की घड़ी में जब पेंटागन के कंधों पर बैठे लोगों द्वारा जनतन्त्र की हत्या की जा रही है तब सचेत लोगों से मानवता क्या माँग कर रही है? सरासर चुप रहना या सचेत समन्वित कारगर कार्रवाई करना? कोई भी जनवादी सोच रखने वाला आदमी जनतन्त्र की हत्या का मूकदर्शक नहीं बना रह सकता है। अत:, सभी देशों के युद्ध-विरोधी शांतिकामी जनवादपसंद देशभक्त लोगों का यह फर्ज बनता है कि वे ऐसे किसी भी हमले के खिलाफ उठ खड़े हों, इसका डट कर मुकाबला करें और अपनी पूरी ताकत के साथ इसे पीछे धकेल दें।

यह खुशी की बात है कि पूरी दुनिया में लोग साम्राज्यवादियों, खासकर अमेरिकी साम्राज्यवादियों की दखलअंदाजियों व हथियारबंद हमलों और दुनिया पर आधिपत्य जमाने के उनके प्रयासों के खिलाफ अपने प्रतिरोध की आवाज बुलन्द कर रहे हैं। वर्तमान विश्व परिदृश्य में एक घटना बहुत ही उत्साहवर्धक है कि अमेरिका, इंग्लैण्ड, जर्मनी, फ्रांस जैसे बड़े साम्राज्यवादी देशों और इज़राइल, तुर्की जैसे उनके दुमछल्ले देशों के मेहनतकश लोग भी अपने-अपने शासकों के युद्धोन्माद के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं और उनकी दूसरे देशों में चोरी छिपे गुप्त कार्रवाइयाँ करने, हिंसा फैलाने की नीति और दूसरे देशों की सार्वभौमता को कुचलने का जोरदार विरोध कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम संघर्षों को सही तरीके से संयोजित किया जाना जरूरी है। किसी देश पर किसी आक्रमण को संगी देशों के मेहनतकश लोगों को उनके खुद पर भी आक्रमण मानना चाहिए। दूसरे शब्दों में उन्हें सिर्फ एकजुटता का इजहार ही नहीं करना होगा बल्कि इससे भी आगे बढ़ कर एकरूपता की भावना से प्रेरित कार्रवाई भी छेड़नी होगी। अगर ईरानी सरकार ने आपसी मतभेदों से ऊपर उठकर साम्राज्यवाद-विरोधी भाईचारे की भावना का इज़हार करते हुए हमलावर अमेरिकी फौज के खिलाफ इराकी प्रतिरोध आन्दोलन में शिरकत की होती और देशभक्त लोगों की अनवादी आकांक्षाओं को अमेरिकी साम्राज्यवाद-विरोधी गुस्से के साथ जोड़ दिया होता तो शायद इतिहास दूसरी ही तरह का लिखा जाता। अब इसे अच्छी तरह समझने का वक्त आ गया है। अमेरिकी लोग भी जो बढ़ते आर्थिक हमले और अपनी सरकार की अनिष्टकारी युद्ध नीति के खिलाफ आवाज बुलन्द कर रहे हैं उन्हें अपने जंगखोर शासकों को इस बात के लिए मजबूर करने के लिए संघर्ष तेज करना चाहिए कि वे दूसरे किसी देश पर आक्रमण करने से बाज आएं क्योंकि पेण्टागन शासन के युद्ध प्रयासों में जितनी तेजी आएगी। जितना युद्ध खर्च बढ़ेगा उतनी ही उनकी कमर टूटेगी क्योंकि इस बढ़ते जा रहे युद्ध खर्च का बोझ उन्हें ही वहन करना पड़ेगा। इसलिए, अन्य देशों में अपने संघर्षरत भाइयों के साथ-साथ अमेरिकी लोगों को भी अपनी सरकार से माँग करनी चाहिए कि ईरान से दूर हटो।

अगर दुनिया भर के संघर्षरत लोगों के बीच वांछित समन्वय और भाईचारा पैदा किया जा सके तो इससे न केवल हरेक देश में साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्षों व जनवादी आन्दोलनों को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि यह काफी हद तक दुश्मन को कमजोर भी कर देगा, साम्राज्यवादी ठगों और महा अपराधियों को झुका देगा तथा उनके षड़यन्त्रों को परास्त कर देगा। एस.यू.सी.आई. (कम्युनिस्ट) सभी का पुरजोर आह्वान करती रही है कि उपरोक्त रास्ते पर चलते हुए एक जोरदार आन्दोलन गठित किया जाए। मानव सभ्यता के इस बड़े नाजुक दौर में इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एस.यू.सी.आई. (कम्युनिस्ट) ने बहुत पहले 1995 में कलकत्ता में आयोजित सम्मेलन में अखिल भारतीय साम्राज्यवाद-विरोधी फोरम गठित करने की पहल की थी जिसमें बहुत से विदेशी प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। सम्मेलन ने विभिन्न देशों के प्रगतिशील व शांतिकामी लोगों का आह्वान किया था कि वे यथासंभव व्यापक आधार वाले साम्राज्यवाद-विरोधी मंच का गठन करने की पहलकदमी करें जिसके जरिये आम सहमति के आधार पर उपयुक्त तौर तरीके व कार्यक्रम निर्धारित किये जाएं। विभिन्न देशों के बिरादराना प्रतिनिधियों और साम्राज्यवाद-विरोधी योद्धाओं ने सुझाव दिया था चूँकि एस.यू.सी.आई. (कम्युनिस्ट) ने यह विचार प्रस्तुत किया है जो सही भी है इसलिए इसे ही एक अन्तर्राष्ट्रीय फोरम गठित करने की पहल करनी चाहिए ताकि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में उभर रहे साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्षों को समन्वित किया जा सके और सभी के बीच संघर्षशील भाईचारा व एकजुटता पैदा की जा सके। इसका अनुसरण करते हुए, हमारी पार्टी ने जिम्मेदारी ली और इण्टरनेशनल एण्टी इम्पीरियलिस्ट एण्ड पीपल्स सोलिडैरिटी को-ऑर्डिनेटिंग कमेटी, जिसका नाम अब इण्टरनेशनल एण्टी इम्पीरियलिस्ट कोऑर्डिनेटिंग कमेटी (आईएसीसी) हो गया है कलकत्ता में आयोजित ऐतिहासिक सम्मेलन में स्थापित की गई। आईएसीसी की दूसरी कॉन्फ्रेन्स जनवरी 2009 में बेरूत में आयोजित की गई। आईएसीसी की तीसरी अन्तर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेन्स ढाका बांग्लादेश में गत नवम्बर महीने में आयोजित की गई थी। कॉन्फ्रेन्स में साम्राज्यवादियों की आधिपत्यवादी व सैन्यीकरण की नीतियों के खिलाफ क्रान्तिकारी संघर्ष छेड़ने का आह्वान किया गया था। कॉन्फ्रेन्स ने सही क्रान्तिकारी नेतृत्व को उभारने की जरूरत पर भी जोर दिया था ताकि साम्राज्यवादी खतरे और तानाशाही, दमनकारी, शोषणमूलक व निरंकुश व्यवस्थाओं के खिलाफ जनसंघर्षों को उनकी तार्किक परिणति तक पहुँचाना सुनिश्चित किया जा सके। हम दुनिया के लोगों का आह्वान करते हैं कि वे इसी के अनुसार काम करें, सुसमन्वित वैश्विक साम्राज्यवाद-विरोधी आन्दोलन का अपराजेय ज्वार पैदा करके अपनी ताकत का इजहार करें ताकि साम्राज्यवाद रूपी इस महाविपत्ति से दुनिया को बचाया जा सके।

ऑल इण्डिया डीवाईओ का म.प्र. राज्य स्तरीय शिक्षण शिविर

आरोन : मध्य प्रदेश के गुना जिले की आरोन तहसील में 8 जनवरी को ऑल इण्डिया डीवाईओ का म.प्र. राज्य स्तरीय शिक्षण शिविर सम्पन्न हुआ। इसका संचालन संगठन की महासचिव कॉमरेड प्रतिभा नायक की देखरेख में हुआ। इसमें संगठन के इन्दौर, ग्वालियर, शिवपुरी, आरोन, बीनागंज, गुना व आरोन के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

शिविर की शुरूआत में संगठन की जरूरत व आज के माहौल के बारे में सवाल-जवाब हुए। ऑल इण्डिया डीवाईओ के जिला अध्यक्ष कॉ. लोकेश शर्मा ने कहा कि बढ़ती बेरोजगारी एक नासूर बन गई है जिसे खत्म करने का एक ही रास्ता है एक जोरदार आन्दोलन खड़ा करना होगा और इस शोषणमूलक व्यवस्था को बदल डालना होगा। शिविर में एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के गुना जिला सचिव कॉमरेड प्रदीप आरबी ने अपने सम्बोधन में कहा कि युग-युग में समाज के नव निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आजादी आन्दोलन के क्रांतिकारियों व नवजागरण काल के मनीषियों ने इस बात को माना था कि युवा शक्ति में सृजनशीलता है और वह समाज का नव निर्माण कर सकती है।

कार्यक्रम की मुख्य वक्ता कॉ. प्रतिभा नायक ने कहा कि जन जीवन की ज्वलंत समस्याओं को लेकर जोरदार आन्दोलन चलाने की जरूरत है। भले ही आज हम संख्या में थोड़े हों लेकिन महान क्रांतिकारी कॉमरेड शिवदास घोष ने कहा है कि शुरूआत करने वाले चंद लोग ही होते हैं। लेकिन सही विचारधारा व मकसद से चलते-चलते वे मेहनतकश जनता को संगठित कर एक बड़ा आन्दोलन खड़ा कर देते हैं। हम भी सही दिशा में आन्दोलन चला कर अश्लीलता, अपसंस्कृति, बेरोजगारी, महंगाई व भ्रष्टाचार को खत्म करने और एक नये समाज का निर्माण करने का प्रयास करेंगे जिसमें मानव द्वारा मानव का शोषण न हो। शहीद भगतसिंह का सपना भी यही था। आज उनके अधूरे सपने को साकार करने की चुनौती हमारे सामने है। अंत में सुनील झण्डा व आरोन इकाई के साथियों द्वारा बाहर से आये हुए नौजवानों का स्वागत किया गया। कॉमरेड शिवदास घोष पर रचित गान के साथ शिविर का समापन हुआ।

R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-01/1123/2012-2014
Posting at IPMBC on 7–8 and 22–23 Fortnightly
Date of Printing : 20 January, 2012

एसयूसीआई (सी), बिहार का शिक्षण शिविर

शिक्षण शिविर का संचालन करते हुए कॉ. रंजीत धर

घाटशिला (झारखंड) : एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) बिहार राज्य कमिटी के तत्वावधान में 24–26 दिसम्बर, 2011 को मार्क्सवाद–लेनिनवाद–शिवदास घोष विचार अध्ययन केन्द्र, घाटशिला (झारखंड) में राजनैतिक शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का प्रारंभ सर्वहारा के महान नेता, इस युग के महान मार्क्सवादी चिंतक, दार्शनिक तथा हमारी प्रिय पार्टी एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के संस्थापक महासचिव कॉ. शिवदास घोष की आदम कद प्रतिमा पर माल्यार्पण के जरिये हुई। शिक्षण शिविर का संचालन एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) पोलित ब्यूरो सदस्य कॉ. रंजीत धर, उत्तर प्रदेश राज्य सांगठनिक कमिटी के वरिष्ठ सदस्य कॉ. स्वपन चटर्जी, बिहार राज्य सचिव कॉ. शिव शंकर तथा राज्य कमिटी के वरिष्ठ सदस्य कॉ. अरूण कुमार सिंह ने किया। शिक्षण शिविर का विषय था–द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद। इस विषय की समझ हासिल करने के लिए कॉमरेडों को गहराई के साथ कॉ. शिवदास घोष की पुस्तकें 'मार्क्सवाद व मानव समाज पर' तथा 'दृष्टिकोण क्या हो', कॉ. माओ–त्से–तुंग की पुस्तक 'अंतर्द्वन्द्व के बारे में और कॉ. स्तालिन की पुस्तक 'ऐतिहासिक व द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद' आदि पढ़कर आने को कहा गया था। शिविर के समापन सत्र को संबोधित करते हुए एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) पोलित ब्यूरो सदस्य कॉ. रंजीत धर ने कहा कि समाज में हर वस्तु और हर घटना परिवर्तन की अवस्था में है। साथ ही मानव मन और मनुष्य का विचार भी परिवर्तनशील है। इसलिए इस परिवर्तनशील जगत में शोषण, अन्याय, अत्याचार पर टिकी पूंजीवादी व्यवस्था भी स्थायी नहीं है। सर्वहारा वर्ग के नेतृत्व में पूंजीवाद–विरोधी समाजवादी क्रांति के जरिये इसका भी परिवर्तन होना अवश्यंभावी है। लेकिन इसके लिए सर्वहारा वर्ग को देश में मौजूद सही सर्वहारा की वर्ग पार्टी के नेतृत्व में अपनी सचेत क्रांतिकारी भूमिका निभानी होगी। जन सवालों को लेकर एक के बाद एक जन आंदोलनों को निर्माण करते हुए वर्ग संघर्ष को तेज करना होगा। उन्होंने कहा कि द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद यानी मार्क्सवाद–लेनिनवाद इस युग का सर्वोन्नत दर्शन है। कॉ. शिवदास घोष ने पूंजीवाद विरोधी समाजवादी क्रांति को संगठित करने के उद्देश्य से देश की ठोस परिस्थिति में मार्क्सवाद–लेनिनवाद को और विकसित, विस्तृत व समृद्ध किया। इसलिए कॉ. शिवदास घोष की रचनाओं का बारीक अध्ययन तथा उसे अपने जीवन में लागू करते हुए उन्नत कम्युनिस्ट बनने का संघर्ष हर नेता–कार्यकर्ता को करने की आज समय की मांग है। शिविर का समापन अंतर्राष्ट्रीय गान तथा कॉ. शिवदास घोष पर रचित गान से हुआ।

मिस्र में हो रहे जुल्मों की एआईएमएसएस द्वारा निन्दा

ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन(एआईएमएसएस) की अध्यक्ष कॉमरेड छाया मुखर्जी व महासचिव कॉमरेड एच. जी. जयालक्ष्मी ने मिस्र में हो रहे जुल्मों की की निन्दा करते हुए 27 दिसम्बर को निम्नलिखित बयान जारी किया : मिस्र में दमनकारी सैनिक शासन के खिलाफ और लोकतंत्र की बहाली के लिए बहादुरी से लड़ रहे आम तौर पर लोगों और खास तौर पर महिलाओं पर हो रहे बर्बर जुल्मों की एआईएमएसएस कड़ी निन्दा करता है। सड़कों पर प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर हो रहे बर्बर हमले देखकर हमे काफी दुख पहुंचा है। बड़ी व्यथा–वेदना के साथ हमने कई संवाद माध्यमों में देखा कि किस तरह एक महिला प्रदर्शनकारी को सड़क पर नंगा कर दिया गया, बुरी तरह से पीटा गया और आन्दोलन में भाग लेने के लिए माफी माँगने पर मजबूर किया गया। उसने चुनाव संचालन में सैनिक शासन के ढकोसले की पोल खोलने के लिए हुए आन्दोलन में भाग लिया था जो चुनाव महज लोगों को झांसा देने के लिए था। यह भी उजागर हुआ है कि पिछले साल फरवरी में महिला प्रदर्शनकारियों के कौमार्य परिक्षण तक भी कराये गये थे। हम स्वेच्छाचारी सैनिक शासन के खिलाफ लड़ रहे मिस्र के बहादुर योद्धाओं और खासकर वहाँ की वीरांगनाओं को अपना क्रांतिकारी अभिनंदन देते हैं। दुनिया के सभी समझदार लोगों से आम तौर पर और महिलाओं से खास तौर पर हम अपील करते हैं कि वे आगे आयें और मानव सभ्यता पर हो रही इस बेइन्तिहा हैवानियत के खिलाफ अपनी आवाज बुलन्द करें।

दिल्ली के स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा

नई दिल्ली: 27 फरवरी को दिल्ली हैल्थ इम्पलाइज़ के आह्वान पर दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग में आर.सी.एच. प्रोजेक्ट पर कार्यरत सैकड़ों नर्सों व पैरामेडिकल स्टाफ ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी शहीद पार्क पर एकत्र हुए और वहाँ से दिल्ली सचिवालय की तरफ बढ़े। उनको आई.टी.ओ. चौक के पास रोक दिया गया। आर.सी.एच. में कार्य करते हुए कर्मचारियों को 10–11 वर्ष बीत गए हैं मगर इनको न तो अब तक पक्का किया गया है और न ही उपयुक्त वेतन व सुविधाएं दी जा रही हैं।

प्रदर्शनकारियों को ज्वाइण्ट प्लेटफार्म ऑफ एक्शन के कार्यकारी अध्यक्ष दीपक धोलकिया, अखिल भारतीय डाट्स कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष रवीन्द्र त्रिपाठी तथा एआईयूटीयूसी के दिल्ली प्रदेश सचिव कॉमरेड हरीश त्यागी ने सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि आर.सी.एच. प्रोजेक्ट बच्चों स्वास्थ्य से जुड़ा अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है मगर इसमें नर्सों व पैरामेडिकल स्टाफ को अभी तक पक्का न किया जाना कर्मचारियों के प्रति दिल्ली सरकारी की उदासीन व नकारात्क मानसिकता का ही परिचायक है। उन्होंने आन्दोलन तेज करने का आह्वान करते हुए कहा कि बिना संघर्ष के न तो नौकरियाँ सुरक्षित होगी और न ही जायज हक मिलेंगे। प्रदर्शनकारियों को हैल्थ इम्पलाइज़ यूनियन की आरसीएच यूनिट की महासचिव निशा, कार्यकारी अध्यक्ष रेणू, कार्यकारिणी सदस्या अंजू, रेखा आदि ने सम्बोधित किया। प्रदर्शनकारियों की ओर से श्रीमति रेणु, सपना, ऋतु व सविता ने दिल्ली के स्वास्थमंत्री श्री अशोक कुमार वालिया से भेंट कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा जिसमें स्वास्थ विभाग में आरसीएच प्रोजेक्ट के तहत पिछले कई सालों से अनुबन्ध पर कार्यरत कर्मचारियों को पक्का करने, वेतन में वृद्धि, डीए, एचआरए सहित भत्ते देने, डीजीएचएस की स्वास्थ सुविधा देने की मांग की गई। मंत्रीजी ने उन्हें सहानुभूतिपूर्वक सुना तथा समस्याएं हल करने का आश्वासन दिया।

रिवाड़ी में महिला सम्मेलन

रिवाड़ी (हरियाणा) : महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन के तत्वावधान में 5 फरवरी को स्थानीय गुजर धर्मशाला में महिला सम्मेलन किया गया। इसकी अध्यक्षता संगठन की नेत्री और आंगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हैल्पर्स यूनियन की जिला सचिव कृष्णा यादव ने की।

सम्मेलन में मुख्य वक्ता दिल्ली महिला सांस्कृतिक संगठन की नेत्री कॉमरेड रितु कौशिक ने कहा कि जब तक महिलाएं स्वयं अपने पैरों पर खड़ी होकर अन्याय–अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठायेंगी तब तक उन पर हो रहे अत्याचार बंद नहीं होंगे। राव आरकेएस कॉलेज ऑफ एज्युकेशन की प्रवक्ता प्रीतिलता और प्रो. इन्दु देवी ने भ्रूण हत्या के साथ–साथ झूठी शान के लिए हो रही ऑनर किलिंग को समाज पर कलंक बताया। मुख्य अतिथि प्रो. अनिरुद्ध ने महिला सम्मेलन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि महिलाओं ने अत्याचारों के खिलाफ जो बीड़ा उठाया है वह प्रशंसनीय है।

इस अवसर पर एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के हरियाणा राज्य सचिव कॉमरेड सत्यवान ने कहा कि महिलाएं दोहरे शोषण की शिकार हैं। इसलिए महिलाओं का संघर्ष ज्यादा गंभीर और जटिल है। महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों की रोकथाम के लिए ताकतवर जुझारू जनआन्दोलन आज समय का तकाजा है। एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के जिला सचिव कॉमरेड राजेन्द्र सिंह ने कहा कि महिलाओं के हित में बनाये गये कानून केवल दिखावा मात्र हैं। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध और अत्याचार रोकने के लिए कई कानून बने हैं लेकिन ये कम होने की बजाय बढ़ रहे हैं। सम्मेलन को सुमन देवी, पूनम, राजबाला, सुषमा और आशा वर्कर यूनियन की नेत्रियों ने भी सम्बोधित किया। सम्मेलन में एक कमेटी का गठन किया गया जिसमें सुमन देवी, पूनम, राजबाला, सुषमा, आशा देवी, सुनीता, संतोष, प्रीतिलता और इन्दु को भी शामिल किया गया।

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया की ओर से कॉ. गिरिजेश्वर सिंह द्वारा 3ए/38, डब्ल्यू.ई.ए., करोल बाग. नई दिल्ली–5 से संपादित व प्रकाशित तथा परम्परा प्रिंटिंग प्रेस, बी–70/83, इण्डस्ट्रियल एरिया, लॉरेंस रोड, दिल्ली–35 से मुद्रित, दूरभाष: 011–25726631, E-mail: sarvaharadrishtikon@yahoo.com